- 19th Year
- Issue: 260
- 28.01.2026 (WEDNESDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISGARH

मदर ऑफ ऑल डील्स पर लगी मुहर, वैश्विक जीडीपी का 25 प्रतिशत हिस्सा कवर

नयी दिल्ली २७/०१ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं के बीच आज नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सज़्मेलन में एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की गई। पीएम मोदी ने इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स (सभी समझौतों की जननी) करार दिया। पीएम मोदी ने समिट के दौरान बताया कि यह समझौता दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को करीब लाता है, जो मिलकर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का एक-तिहाई (1/3) हिस्सा कवर करते हैं।

2 अरब लोगों का बाजार- यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि इस समझौते से 2 अरब लोगों का एक विशाल एकीकृत बाजार तैयार होगा। रक्षा और सुरक्षा साझेदारी- व्यापार के अलावा, दोनों पक्षों ने एक रणनीतिक रक्षा और सुरक्षा साझेदारी (स्ष्ठक्क) पर भी हस्ताक्षर किए। यह भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय संघ के 150 अरब यूरो के रक्षा कार्यक्रम में भागीदारी के द्वार खोलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत-ईयू व्यापार समझौता कई लोगों के लिए अवसर पैदा करके भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेज़्टर को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लंबित भारत-ईयू व्यापार समझौते को दुनिया भर के लोग पहले से ही सभी सौदों की जननी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह समझौता लोकतंत्र और कानून के शासन के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है। यूरोपीय संघ के साथ यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और श्वस्नञ्ज के समझौतों को भी पूरा करेगा। मैं इसके लिए देश के लोगों को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कल यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच एक बड़ा समझौता हुआ। लोग इसे सभी डील्स की जननी कह रहे हैं। यह समझौता भारत और यूरोप के लोगों के लिए बड़े मौके लाएगा। यह दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है... यह समझौता ग्लोबल त्रष्ठक्क का 25 परसेंट और ग्लोबल ट्रेड का 1/3 हिस्सा दिखाता है।

इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच टेज़्नोलॉजी और रक्षा पार्टनरशिप पर साइन होना, एक जटिल ग्लोबल माहौल में दोनों पक्षों को करीब लाने की दिशा में एक अहम कदम है। रक्षा मंत्रालय, साउथ ज़्लॉक में श्व के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के हाई रिप्रेजेंटेटिव काजा कैलास के नेतृत्व वाले श्व प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए, सिंह ने श्व नेताओं के दौरे का स्वागत किया और इसके खास महत्व पर जोर दिया, ज़्योंकि यह भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हो रहा है।

सिंह ने कहा, भारत आने के लिए धन्यवाद, आपका दौरा बहुत खास है ज़्योंकि यह हमारे 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हो रहा है। यह मौका भारत की संवैधानिक यात्रा के जश्न में एक मील का पत्थर है और ग्लोबल शांति और सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र, बहुलवाद, संघवाद और कानून के शासन के साझा मूल्य यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की बढ़ती पार्टनरशिप की नींव बनाते हैं। साथ मिलकर हमारा लक्ष्य इन साझा मूल्यों को ग्लोबल सुरक्षा, सस्टेनेबल विकास और समावेशी समृद्धि के लिए व्यावहारिक सहयोग में बदलना है।

उज़्राखंड के गंगोत्री धाम में गैर-हिंदुओं पर रोक? फैसले पर गरमाई राजनीति

देहरादून २७/०१ (संवाददाता): श्री गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत अब उज़्राखंड के गंगोत्री धाम में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, यह प्रतिबंध देवता के शीतकालीन निवास मुखबा पर भी लागू होगा। इसके साथ ही, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम सहित समिति के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों में भी गैर-हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने जानकारी दी है कि वे जल्द ही एक प्रस्ताव भेज रहे हैं, जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ के साथ-साथ अन्य सभी संबंधित मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव को आने वाली बोर्ड बैठक में औपचारिक रूप से पेश किया जाएगा।

उज़्राखंड सरकार हरिद्वार के घाटों पर भी गैर-हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रही है। हरिद्वार, जो कि 120 वर्ग किमी में फैला एक अत्यंत पवित्र शहर है, के 105 घाटों के संबंध में यह कदम उठाया जा सकता है। संतों और गंगा सभा के अनुरोध पर सरकार हरिद्वार और ऋषिकेश को आधिकारिक रूप से सनातन पवित्र शहर घोषित करने की योजना भी बना रही है।

इस संवेदनशील मुद्दे पर मुज़्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार धार्मिक स्थलों से जुड़े कानूनों की समीक्षा करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि फैसला लेने से पहले सभी हितधारकों, जैसे तीर्थयात्रा समितियों के सदस्यों और प्रबंधन से जुड़े लोगों के विचारों और राय पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

इस फैसले को लेकर राजनीति भी गरमा गई है। पूर्व मुज़्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास अब कोई चुनावी मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए ऐसे नए एजेंडे बनाए जा रहे हैं। वहीं, भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने मंदिर की छवि खराब होने का हवाला देते हुए पहले ही इस प्रतिबंध की मांग की थी। हालांकि, यह भी चिंता का विषय है कि कई गैर-हिंदू लोग इन क्षेत्रों में पर्यटन के जरिए अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 29 को, 1 फरवरी को केंद्रीय बजट-किरेन रिजिजू

नयी दिल्ली २७/०१ (संवाददाता): भारत के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक समाप्त होने के बाद बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी, 2026 को प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि विज़ीय वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी, 2026 को प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में 39 विभिन्न राजनीतिक दलों के 51 सदस्यों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार की ओर से सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि हमारी संसदीय लोकतंत्र में हमें जनता की ओर से बोलने, जनता का प्रतिनिधित्व करने और जनता के लिए बोलने के लिए चुना गया है। इसलिए, बोलने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, हमारा यह कर्तव्य भी है कि हम अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों की बात सुनें ताकि हमारी संसदीय लोकतंत्र पूरी जीवंतता के साथ कार्य करती रहे।

रिजिजू ने बताया कि सर्वदलीय नेताओं की बैठक के दौरान कई सदस्यों ने अनेक मुद्दे उठाए। हमने उन्हें नोट कर लिया है, और मैंने सदस्यों से यह भी अनुरोध किया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान, बहस और चर्चा में विभिन्न मुद्दों को उठाया जा सकता है और उन पर चर्चा की जा सकती है, और बजट के दौरान भी, ज़्योंकि बजट सत्र का पहला भाग पूरी तरह से राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव के लिए समर्पित होगा। चूंकि यह बजट सत्र है, इसलिए इस सत्र का मुज़्य केंद्र बजट ही होगा।

रिजिजू ने यह भी कहा कि मैं इस मामले को पूरी तरह स्पष्ट करना चाहता हूँ। पिछली बार, कई राजनीतिक दलों, बल्कि सभी विपक्षी दलों ने एसआईआर पर चर्चा की मांग की थी और सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया था। हमने चुनाव सुधारों का मुद्दा उठाया था, जिसमें एसआईआर का मुद्दा भी शामिल था, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस पर लंबी और विस्तृत चर्चा हुई थी। अन्य सभी सदस्यों को पर्याप्त समय दिया गया था। वास्तव में, सभी दलों ने आवंटित समय में अपनी चर्चा पूरी करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी थी। यदि वे फिर से बहस की मांग करते हैं, तो यह अनावश्यक होगा ज़्योंकि इस पर पहले ही विस्तार से चर्चा हो चुकी है।

रिजिजू ने कहा कि नियमों के अनुसार, चर्चा केवल बजट पर ही केंद्रित होनी चाहिए।

श्रीनगर में भारी बर्फबारी! विजिबिलिटी कम होने से कई उड़ानें रद्द

श्रीनगर २७/०१ (संवाददाता): कश्मीर घाटी में हो रही ताजा बर्फबारी के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दृश्यता कम होने और रनवे पर बर्फ जमा होने के कारण कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। हवाई अड्डा प्रशासन ने बताया कि रनवे से बर्फ हटाने का काम जारी है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी के कारण इसमें बाधा आ रही है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपने घर से निकलने से पहले संबंधित एयरलाइंस से उड़ान की स्थिति (Flight Status) की जांच जरूर कर लें।

भारतीय विमानपज़न प्राधिकरण के एक अधिकारी ने कहा, ''श्रीनगर हवाई अड्डे पर प्रतिकूल मौसम की स्थिति और लगातार बर्फबारी को देखते हुए एयरलाइंस ने आज कुछ उड़ानें रद्द कर दी हैं।'' अब तक कुल 16 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिनमें आठ यहां आने वाली और आठ यहां से प्रस्थान करने वाली उड़ानें शामिल हैं। अधिकारी ने बताया, ''यात्रियों को नवीनतम जानकारी और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए अपनी-अपनी एयरलाइन के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है।'' उड़ानों के रद्द होने से सैकड़ों पर्यटक कश्मीर में फंस गए हैं, जो सप्ताहांत और गणतंत्र दिवस की छुट्टियां घाटी में बिताने के बाद लौटने वाले थे।

महाराष्ट्र का महाकीर्तिमान, 2 करोड़ छात्रों ने एक साथ देशभक्ति गीत गाकर रचा विश्व रिकॉर्ड

मुंबई २७/०१ (संवाददाता): महाराष्ट्र के एक लाख स्कूलों के दो करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने राष्ट्र प्रथम पहल के तहत, गणतंत्र दिवस पर एक साथ देशभक्ति गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' ने इस पहल को आधिकारिक तौर पर दर्ज कर लिया है जिससे यह विश्व रिकॉर्ड बन गया है। भुसे ने कहा कि राष्ट्र प्रथम पहल के तहत एक लाख स्कूल के दो करोड़ से अधिक छात्रों ने एक साथ देशभक्ति गीतों पर अनुशासित और समन्वित प्रस्तुति दी। सात लाख शिक्षकों ने भी इसमें भाग लिया।राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने इस ऐतिहासिक उपलज़्धि की आधिकारिक पुष्टि की। उन्होंने बताया कि 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' ने इस पहल की भव्यता और समन्वय को देखते हुए इसे आधिकारिक तौर पर वैश्विक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज कर लिया है।विद्यार्थियों की भागीदारी- राज्य भर के विभिन्न स्कूलों से 2 करोड़ से अधिक छात्र इस सामूहिक गान का हिस्सा बने।शिक्षकों का सहयोग- इस विशाल आयोजन को सफल बनाने में लगभग 7 लाख शिक्षकों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई और छात्रों के साथ सुर मिलाया।अनुशासन और समन्वय- शिक्षा मंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि इतनी बड़ी संज़्या होने के बावजूद, छात्रों की प्रस्तुति पूरी तरह से अनुशासित और समन्वित थी। यह आयोजन केवल संज़्या के लिहाज से बड़ा नहीं था, बल्कि इसका मुज़्य उद्देश्य बच्चों के मन में %राष्ट्र प्रथम% की भावना को जागृत करना था। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर, महाराष्ट्र के हर कोने से गूंजते देशभक्ति के सुरों ने एकता का एक शक्तिशाली संदेश दिया है।

असम दिखावे के लिए नहीं, जवाबदेही के लिए वोट करेगा-पवन खेड़ा

२७/०१ (संवाददाता): कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की पूर्वोज़र के संकटकालीन समय में वहां के लोगों के साथ खड़े रहने की सराहना की, वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ध्यान भटकाने वाली रणनीति की कड़ी आलोचना की। सोमवार को ङ्ग पर एक पोस्ट में, खेड़ा ने गांधी की पूर्वोज़र के नागरिकों से बातचीत करते हुए तस्वीरें साझा कीं और चुनौतीपूर्ण समय में इस क्षेत्र के लिए खड़े होने में कांग्रेस नेता के चरित्र और नैतिक साहस की प्रशंसा की।पूर्वोज़र की मदद में कांग्रेस के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, खेड़ा ने आरोप लगाया कि भाजपा-आरएसएस तंत्र ने मणिपुर हिंसा और जुबीन गर्ग की मौत की जांच का हवाला देते हुए, सात बहनों के लिए शांति और सज़्मान को सक्रिय रूप से नष्ट किया है।

खेड़ा ने असम के मुज़्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की सीधी आलोचना करते हुए उन पर राज्य की गंभीर समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए दिखावे की आड़ में छिपने का आरोप लगाया।

उन्होंने ङ्ग पर लिखा कि राहुल गांधी ने पूर्वोज़र के हमारे भाइयों और बहनों के साथ खड़े होने का साहस और नैतिक साहस दिखाया है - मणिपुर के साथ, जो प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति और चुप्पी के बीच जल रहा था; जुबीन गर्ग के परिवार के साथ, जो अभी भी जवाब का इंतजार कर रहा है; और एंजेल चकमा के परिवार के साथ, जो अभी भी न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। खेड़ा ने आगे लिखा, ऋयह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हिमंता बिस्वा दिखावे की आड़ में छिप रहे हैं ज़्योंकि उन्हें पता है कि उनके दिन गिने-चुने हैं। पूर्वोज़र शांति, न्याय, रोजगार और अपनी समृद्ध और जटिल संस्कृति के सज़्मान की मांग करता है - ये वो चीजें हैं जिन्हें भाजपा-आरएसएस के तंत्र ने सक्रिय रूप से नष्ट कर दिया है। खेड़ा ने इस बात पर और जोर दिया कि असम के मतदाता दिखावे की बजाय जवाबदेही को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने अपने पोस्ट का समापन करते हुए कहा कि असम दिखावे के लिए वोट नहीं दे रहा है। यह जवाबदेही के लिए वोट दे रहा है।

छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बीच धर्मेंद्र प्रधान का आश्वासन, कानून का दुरुपयोग नहीं होगा

नयी दिल्ली २७/०१ (संवाददाता): केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी 2026 के नए नियमों को लेकर उठ रही चिंताओं को दूर करते हुए बड़ा बयान दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि कोई भेदभाव नहीं होगा और कोई भी इस कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकता। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ये नियम उच्च शिक्षा में निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं और उन्होंने शिक्षण संस्थानों से इन्हें जिमेदारी से लागू करने का आग्रह किया। उनकी ये टिप्पणी देश भर में नए नियमों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों और बहसों के बीच आई है, जिसमें समर्थक और विरोधी दोनों ही अपनी-अपनी राय खुलकर व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी ओर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूएनआई) द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम, 2026 को लेकर व्यापक विरोध के बाद, शिक्षा मंत्रालय से इन विनियमों के संबंध में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं पर विस्तृत जवाब जारी करने की उज़्मीद है। 13 जनवरी, 2026 को अधिसूचित ये विनियम, 2012 के पूर्व ढांचे का स्थान लेते हैं और भारतीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भेदभाव से निपटने के लिए प्रक्रियाओं को संस्थागत रूप देने का दावा करते हैं।

हालांकि, नए नियमों को लेकर व्यापक आलोचना और विरोध प्रदर्शनों का सामना करने के बाद, शिक्षा मंत्रालय अब स्पष्टीकरण जारी करने की तैयारी कर रहा है। खबरों के अनुसार, सरकार यह आश्वासन देगी कि नियमों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा और शैक्षणिक परिसरों में भेदभाव को रोकने के लिए एक तंत्र उपलज़्ध कराएगी।

सामान्य वर्ग के छात्रों ने दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मुज़्यालय के बाहर मंगलवार को प्रदर्शन का आह्वान करते हुए कहा कि आयोग द्वारा जारी नए विनियम परिसरों में अराजकता पैदा कर सकते हैं। प्रदर्शन का आह्वान करने वालों ने छात्र समुदाय से एकजुटता की अपील की, उनसे ''यूजीसी के भेदभाव को ना'' कहने का आग्रह किया और बड़ी संज़्या में इकट्ठा होकर अपना विरोध दर्ज कराने का अनुरोध किया। यूजीसी द्वारा 13 जनवरी को अधिसूचित 'उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम, 2026' की सामान्य श्रेणी के छात्रों ने व्यापक पैमाने पर आलोचना की है और उनका तर्क है कि यह ढांचा उनके खिलाफ भेदभाव का कारण बन सकता है। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जाति-आधारित भेदभाव रोकने के लिए लाए गए नए विनियमों के तहत यूजीसी ने संस्थानों से शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और निगरानी दल गठित करने को कहा है ताकि खासकर अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों की शिकायतों का समाधान किया जा सके।

दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी के छात्र आलोकित त्रिपाठी ने कहा कि नए नियमों से महाविद्यालयों में पूरी तरह अराजकता पैदा हो जाएगी ज़्योंकि अब प्रमाण का बोझ पूरी तरह आरोपी पर डाल दिया जाएगा और गलत आरोप झेलने वाले छात्रों के लिए कोई सुरक्षा प्रावधान नहीं है।

विविध समाचार

ऐतिहासिक भारत और यूरोपीय संघ व्यापार समझौते पर लगी मुहर, विदेश मंत्रालय ने बताया गेम चेंजर सौदा

नयी दिल्ली २७/०१ (संवाददाता): जिस दिन भारत और यूरोपीय संघ ने एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे %सभी समझौतों की जननी% बताया जा रहा है, उसी दिन विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल की ऐतिहासिक यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। राष्ट्रीय राजधानी में एक ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, मिसरी के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने पारस्परिक लाभ के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है।

इसके परिणाम गहन रूप से रणनीतिक प्रकृति के हैं। पिछले एक दशक में भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच संपर्कों और गतिविधियों के स्तर और आवृज़ि से स्पष्ट होता है कि ये संबंध न केवल व्यापक हैं बल्कि इनका महत्व भी बढ़ा है।

तेजी से बदलती दुनिया में भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी का महत्व द्विपक्षीय संदर्भ से कहीं अधिक है, विशेष रूप से जब हम वैश्विक आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक परिदृश्य में बदलाव देख रहे हैं। दुनिया के दूसरे और चौथे सबसे बड़े बाजारों के रूप में, भारत और यूरोपीय संघ की आज की सभी महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों में गहरी हिस्सेदारी है, जिनमें वैश्विक विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सीमित भौगोलिक क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भरता और संकेंद्रण, एक अप्रभावी बहुपक्षीय प्रणाली, उभरती बहुध्रुवीयता और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बढ़ती संरक्षणवादी प्रवृज़ियां शामिल हैं। इसलिए, दो बड़े बहुलवादी लोकतंत्रों और खुली बाजार अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारे नेताओं ने पारस्परिक लाभ और समग्र रूप से वैश्विक आबादी के व्यापक हित के लिए इस रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है।

विदेश सचिव ने कहा कि यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौते के साथ-साथ दोनों पक्षों के बीच कई अन्य महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रपति एंटोनियो कोस्टा और राष्ट्रपति उर्सुला वॉन डेर लेयेन और प्रधानमंत्री मोदी ने 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सज़्मेलन की सह-अध्यक्षता की।

उन्होंने सीमित प्रारूप और प्रतिनिधिमंडल स्तर के प्रारूप दोनों में विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता की। नेताओं के समक्ष कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान-प्रदान किया गया, जिनमें ऐतिहासिक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता के समापन की संयुक्त घोषणा, दोनों पक्षों के बीच एक समान रूप से महत्वपूर्ण सुरक्षा और रक्षा साझेदारी समझौता और गतिशीलता पर सहयोग के व्यापक ढांचे पर एक समझौता ज्ञापन आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वॉन डेर लेयेन ने भारत मंडपम में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार मंच को भी संबोधित किया, जिसमें दोनों पक्षों के 100 से अधिक सीईओ ने भाग लिया। मिसरी ने यूरोपीय संघ के राष्ट्रपतियों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह पहली बार है जब यूरोपीय संघ के नेता गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हैं।

वैश्विक व्यापार में नया संतुलन-ब्रिटेन-चीन, भारत-कनाडा और ब्राजील की सक्रिय कूटनीति

नयी दिल्ली २७/०१ (संवाददाता): वैश्विक कूटनीति एक नए संतुलन की ओर बढ़ती दिख रही हैं। बदलते अंतरराष्ट्रीय व्यापार माहौल के बीच कई बड़े देश अपने पुराने रिश्तों की मरज़्मत और नए साझेदारों की तलाश में सक्रिय हो गए हैं।

मौजूद जानकारी के अनुसार, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर मंगलवार शाम चीन के लिए रवाना होने वाले हैं, जहां वह बीजिंग और शंघाई में शीर्ष नेतृत्व और कारोबारी जगत से मुलाकात करेंगे हैं। यह दौरा बीते आठ वर्षों में किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री की चीन यात्रा होगी, जिसे लंदन-बीजिंग संबंधों में नए सिरे से संवाद की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा हैं। बता दें कि स्टारमर के साथ कई बड़े उद्योगपति और दो वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होंगे, जो व्यापार, निवेश और सप्लाई चेन सहयोग पर बातचीत करेंगे हैं।इसी कड़ी में एक और पूर्व-पश्चिम समीकरण उभरता दिख रहा हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च में भारत के दौरे की तैयारी में हैं, जहां भारत-कनाडा व्यापार को तेज़ी से विस्तार देने पर जोर रहेगा हैं। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में राजनीतिक तनाव के बावजूद दोनों देश आर्थिक रिश्तों को प्राथमिकता देने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं।इस बदलते परिदृश्य की पृष्ठभूमि में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हालिया हस्ताक्षर अहम माने जा रहे हैं, जो करीब दो अरब आबादी वाले बाजार को जोड़ता हैं। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा 19 से 21 फरवरी के बीच भारत दौरे पर आने वाले हैं। बता दें कि उनके साथ एक बड़ा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल होगा और भारतीय उद्योग जगत से संवाद के लिए दो दिन तक 500 सीटों वाला सभागार भी बुक किया गया। गौरतलब है कि इन तमाम कूटनीतिक गतिविधियों के पीछे एक साझा कारण उभर कर सामने आ रहा हैं, और वह है वैश्विक व्यापार में जोखिम कम करने और विकल्पों को विविध बनाने की जरूरत हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियों और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों ने कई देशों को नए साझेदार तलाशने के लिए मजबूर किया।

ब्रिटेन का चीन की ओर झुकाव भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा हैं। स्टारमर की यह यात्रा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक संदेश भी देती हैं, जिसमें यह साफ़ संकेत है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में देश एक-दूसरे पर निर्भरता को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में एसआईआर की आड़ में एनआरसी करा रही बीजेपी-अखिलेश यादव

नयी दिल्ली २७/०१ (संवाददाता): समाजवादी पार्टी (एसपी) के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को दावा किया कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई), सज़ारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ मिलकर, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की आड़ में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) अभियान चला रहा है और साथ ही आम जनता को परेशान कर रहा है। उन्होंने आगे दावा किया कि ईसीआई यह एसआईआर अभियान केवल पश्चिम बंगाल के लिए चला रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के पहले छमाही में होने की उज़्मीद है। यहाँ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की जिज़्मेदारी है कि वह मतदान में वृद्धि सुनिश्चित करे, लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग और भाजपा, एसआईआर की आड़ में, एनआरसी चला रहे हैं और आम जनता को परेशान कर रहे हैं, और उनका उद्देश्य अधिक वोटों की कटौती करना है। जबकि उनकी जिज़्मेदारी मतदाताओं की मदद करना है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रशंसा करते हुए

कहा कि पूरे देश में अगर कोई भाजपा को टक्कर दे रहा है, तो वह ममता बनर्जी ही हैं। यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि पश्चिम बंगाल की जनता भाजपा को हराएगी और ममता बनर्जी फिर से मुज़्यमंत्री बनेंगी। 卐अगर कोई भाजपा को टक्कर दे रहा है, तो वो मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। भाजपा द्वारा लाया गया एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) केवल पश्चिम बंगाल के लिए है, हालांकि इसे बिहार में भी लागू किया गया था।

सपा प्रमुख ने कहा कि जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अभियान चलाता है, लेकिन एसआईआर के नाम पर ठीक उल्टा हो रहा है। बंगाल में एसआईआर के नाम पर मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी को परेशान किया जा रहा है। देश में अतीत में एसआईआर के नाम पर किसी को परेशान नहीं किया गया। मुझे विश्वास है कि वह फिर से मुज़्यमंत्री बनेंगी। बंगाल की जनता भाजपा को हराएगी। वे हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उज़र प्रदेश में अधिक वोट काटे जा रहे हैं। मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी को हरा दिया है। भाजपा %पेन ड्राइव% कांड के दर्द से उबर नहीं पाई है।

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला करते हुए उस पर लोगों के मतदान अधिकार छीनने का आरोप लगाया।एज़्स पर एक पोस्ट में ममता बनर्जी ने कहा कि वह चुनाव आयोग के आचरण से गहराई से व्यथित हैं और आरोप लगाया कि चुनाव निकाय मतदाता सूचियों में तार्किक विसंगति के नाम पर लोगों को परेशान कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है, और यह कितना दुखद तमाशा है!

जयशंकर ने अमेरिकी संसदीय दल से की वार्ता, हिंद-प्रशांत क्षेत्र और यूक्रेन मुद्दे पर हुई बात

नई दिल्ली २७/०१ (संवाददाता):भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक स्तर पर जारी तनाव के दौर में विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने तीन सदस्यीय अमेरिकी संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जिसमें व्यापार और सुरक्षा के मुद्दे अहम रहे हैं। इसके अलावा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के कई पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने इस बातचीत को भारत और अमेरिका के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू बताया। विदेश मंत्री जयशंकर के साथ रविवार को बैठक में उपस्थित अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि बातचीत %फलदायी% रही और इसका ध्यान सुरक्षा, व्यापार और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर था।

विदेश मंत्री जयशंकर ने एक पोस्ट को साझा किया कि उन्होंने अलबामा के प्रतिनिधि माइक रोजर्स, वाशिंगटन के एडम स्मिथ और ज़्लोरिडा के जिमी पैट्रोनिस के साथ बातचीत की। साथ ही भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से भी चर्चा की। राजदूत गोर ने बैठक को फलदायी बताया और कहा कि यह भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत सुरक्षा, विस्तारित व्यापार और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर सहयोग के लिए बढ़ावा देगा। यह बैठक नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच उच्च-स्तरीय बातचीत की एक श्रृंखला के बीच हुई है।

दिल्ली में साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा, %%यह बातचीत 13 जनवरी को हुई।

गणतंत्र दिवस पर सीट को लेकर भाजपा-कांग्रेस में महाभारत, खरगे ने लगाए गंभीर आरोप

नयी दिल्ली २७/०१ (संवाददाता): गणतंत्र दिवस समारोह में बैठने की व्यवस्था को लेकर मंगलवार को भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भाजपा पर 2016 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए जानबूझकर विपक्ष का अपमान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर दो विपक्षी नेताओं को समारोह के दौरान तीसरी पंक्ति में बैठाकर संविधान का अपमान करने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित स्वागत समारोह के दौरान असमिया गमोसा को लेकर उठे विवाद पर भी स्पष्टीकरण दिया।

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राहुल गांधी ने %गमोसा% पहना था। खाना खाते समय उन्होंने उसे मोड़कर रख दिया। भाजपा इसे मुद्दा बना रही है। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान दो विपक्षी नेताओं को तीसरी पंक्ति में बैठाकर वे संविधान का अपमान कर रहे हैं। हम भी राज्य मंत्रियों के साथ भारत के राष्ट्रपति से मिलने के लिए कतार में खड़े थे। वे जानबूझकर विपक्ष का इतना अपमान कर रहे हैं... मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं जब वे (भाजपा) कहते हैं कि कांग्रेस पूर्वोज़र का अपमान करने के लिए ऐसा कर रही है। वे ऐसा सिर्फ कांग्रेस को अपमानित करने और आगामी चुनावों के लिए कर रहे हैं।

खरगे ने कहा कि मैं सबसे वरिष्ठ नेता हूं, वे मुझे तीसरी पंक्ति में और राज्य मंत्रियों के साथ कैसे बिठा सकते हैं? आपने मेरा, कांग्रेस का और संविधान का अपमान किया है। इससे पहले, भाजपा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित गृह सज़्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अनुरोध के बावजूद पटका न पहनने के कारण राहुल गांधी पर पूर्वोज़र की संस्कृति और लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया था। असम के मुज़्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी के इस कदम की कड़ी निंदा की और कहा कि इससे उज़र के प्रति उपेक्षा की भावना और मजबूत होती है।

भाजपा नेताओं के अनुसार, राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों सहित गृह स्वागत समारोह में सभी ने पटका पहना था। असम के मुज़्यमंत्री ने ङ्ग पर एक पोस्ट में कहा, 卐समय बदल सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वास्तविक सर्वोच्च नेता राहुल गांधी का रवैया अफसोसजनक रूप से अपरिवर्तित प्रतीत होता है। पूर्वोज़र के लोगों के प्रति घोर असंवेदनशील और अपमानजनक कृत्य करते हुए, गांधी ने आज शाम भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक पारंपरिक पटका को नहीं पहना।

पश्चिम बंगाल: दक्षिण 24 परगना के गोदामों में भीषण आग, 8 लोगों की दर्दनाक मौत

कोलकाता२७/०१ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहाँ सोमवार को दो गोदामों में लगी भीषण आग ने कम से कम आठ लोगों की जान ले ली। यह हादसा कोलकाता के नरेन्द्रपुर थाना क्षेत्र के नजीराबाद इलाके में हुआ।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, नजीराबाद में स्थित दो गोदाम, जो एक-दूसरे के बिल्कुल बगल में थे, अचानक आग की लपटों में घिर गए। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को लगभग सात घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान करीब पांच बजे घटनास्थल से तीन शव बरामद किए गए और बाद में पांच अन्य शवों को ढूंढ निकाला गया।

बारुईपुर जिले के पुलिस अधीक्षक शुभेंदु कुमार ने बताया कि शव बुरी तरह झुलसे होने के कारण अभी मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि मलबा पूरी तरह से साफ होने के बाद ही पता चल पाएगा कि संबंधित स्थल पर कोई और शव तो नहीं है या मलबे में कोई व्यक्ति फंसा तो नहीं है। पुलिस ने बताया कि शुरुआत में छह लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी लेकिन फंसे हुए लोगों के परिवारों के मुताबिक यह संज़्या 10 से अधिक हो सकती है ज़्योंकि पास के गोदामों में साज सज्जा का काम करने वाली एक कंपनी और मोमो बेचने वाली एक कंपनी के मजदूर काम करते थे।

अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस ने बताया कि बचाव अभियान जारी है। बोस ने दो इकाइयों के प्रबंधन द्वारा अपनाए जा रहे अग्नि सुरक्षा नियमों के बारे में पूछे जाने पर कहा, वर्ष में दो बार अग्नि सुरक्षा ऑडिट किया जाता है और हर खामी को दूर किया जाता है, फिर भी मालिकों व कंपनी के अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करें।卐 जैसे ही शाम ढलने लगी, मृतकों और लापता व्यक्तियों के कई रिश्तेदार घटनास्थल पर जमा हो गए और अग्निशमन सेवा एवं पुलिस अधिकारियों से स्थिति की जानकारी लेने लगे।

तन्मय गिरि नाम के एक व्यक्ति ने बताया, 卐पूर्वी मेदिनीपुर के तमलुक के रहने वाले मेरे चाचा गोदाम के अंदर बने छोटे कमरों में रह रहे थे। वे एक कंपनी में काम करते थे। उन्होंने आखिरी बार रात करीब एक बजे फोन किया था और अब उनका फोन बंद है।卐 उसने कहा कि वह सुबह नौ बजे से उनका फोन आने का इंतजार कर रहा है। एक अन्य युवक ने बताया कि उसके पिता मोमो बनाने की एक इकाई में रात्रि पाली में काम के लिये आए थे और तब से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। मृत या लापता सभी लोग पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना जिलों के निवासी हैं।घटनास्थल का दौरा करने वाले बिजली मंत्री अरूप बिस्वास ने इन दावों के बीच पत्रकारों से कहा कि घना धुआं छंटने के बाद ही यह पुष्टि की जा सकेगी कि कोई अंदर फंसा हुआ है या नहीं। उन्होंने कहा, ''कोलकाता नगर निगम की टीम को दीवारों को तोड़ने और धुआं बाहर निकालने के लिए बुलाया गया है।'' बिस्वास ने कहा कि जब दमकलकर्मी और पुलिसकर्मी गोदाम में प्रवेश कर सकेंगे, तभी यह पुष्टि हो पाएगी कि अंदर कोई फंसा हुआ है या नहीं। अधिकारी ने बताया कि देर रात तीन बजे आग लगने की सूचना मिली और इसे दमकल की 12 गाड़ियों की मदद से बुझाया गया। आग पर सुबह करीब 10 बजे काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है और इससे हुए नुकसान का आकलन भी अभी नहीं हुआ है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर 'इतनी भीषण आग के दौरान आपदा प्रबंधन में असंवेदनशीलता और समन्वय की कमी' का आरोप लगाया।उन्होंने कहा, 卐मंत्री और वरिष्ठ सरकारी एवं पुलिस अधिकारी गणतंत्र दिवस की छुट्टी मना रहे हैं और गरीबों की उन्हें कोई चिंता नहीं है। यह सरकार जितनी जल्दी जाए, उतना ही अच्छा है।卐 बिस्वास ने अधिकारी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 卐यह घटना पर राजनीति करने का समय नहीं है।卐 पिछले साल 30 अप्रैल को मध्य कोलकाता के एक होटल में लगी आग में 14 लोगों की मौत हो गई थी।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

विविध समाचार

जमी नदी में मछलियां पकड़ रहे हज़ारों लोग, तीन साल बाद दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ फेस्टिवल

दक्षिण कोरिया में आइस फेस्टिवल शुरू हुआ है यह वास्तव में मछली पकड़ने का फेस्टिवल है, जो कि दक्षिण कोरिया के गंगवान प्रांत की नदी पर हो रहा है।

यह नदी भीषण सर्दी से पूरी तरह जम चुकी है। नदी की ऊपरी सतह पर 6 इंच मोटी बर्फ की परत जम गई है। जनवरी में इस इलाके का तापमान माइनस 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस फेस्टिवल में हजारों लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस फेस्टिवल के दौरान लोग नदी पर जमी बर्फ में छेद करते है। फिर हाथ या कांटे से मछली पकड़ते हैं।

क्या है दशकों पुराना केसलर सिंड्रोम

स्पेस से क्या है इसका कनेक्शन?

अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा किसलर सिंड्रोम पैदा करने के हालात बना रहा है. अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा किसलर सिंड्रोम पैदा करने के हालात बना रहा है. स्पेस में कचरे के कारण पैदा होने वाली समस्या का अनुमान दशकों पहले ही लगा लिया गया था. नासा के एक वैज्ञानिक ने इससे पैदा होने वाले एक चरम हालात को एक सिंड्रोम की तरह परिभाषित किया था. वैज्ञानिक मानते है कि आज पृथ्वी की निचली कक्षा इस स्थिति के शुरुआती चरण में पहुंच चुकी है.

स्पेस बहुत बड़ा इलाका है और यहां तक कि पृथ्वी की निचली कक्षा भी. हम अब तक हजारों सैटेलाइट स्पेस में भेज चुके है और उनमें से बहुत से खराब होकर वहीं रह गए हैं और वे और उनके टुकड़े कचरे के तौर पर वहीं रह कर पृथ्वी का चक्कर लगा रहे है. पर क्या यह कचरा दूसरे सैटेलाइट्स के लिए खतरा है? हां बिलकुल पर कितना बड़ा? यह बहस का विषय है. लेकिन उतनी ही चिंता का भी. हमारे वैज्ञानिकों ने दशकों पहले इस खतरे को लेकर चेताना शुरू कर दिया था और यहीं केसलर सिंड्रोम का नाम आता है. आइए जानते है कि यह केसलर सिंड्रोम क्या है और इसका इस कचरे से क्या संबंध है?

क्या है केसलर सिंड्रोम

अंतरिक्ष के खतरे को 1970 के दशक से ही पहचान लिया गया था. नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड केसलर ने 1978 में एक काल्पनिक स्थिति का प्रस्ताव दिया था जो भविष्य में कभी ना कभी जरूर आ सकती थी. और अब वह जल्दी ही आ जाएगी ऐसा माना जाने लगा है. इस स्थिति में पृथ्वी की निचली कक्षा में टकराव की घटनाएं शुरू हो जाएगी जिसमें सैटेलाइट, अंतरिक्ष यान, रॉकेट आदि टकराकर टूटेंगे और ज्यादा कचरा पैदा कर टकरावों की घटनाओं का ऐसा सिलसिला चला देंगे जो कभी खत्म ही नहीं होगा. इसके बाद हालात ऐसे हो जाएंगी कि कक्षा में कचरा इतना भर जाएगा, भावी पीढ़ी के लिए उसका इस्तेमाल संभव ही नहीं रह जाएगा.

क्या होगा इससे

इसका सबसे बड़ा नतीजा यही होगा कि वो सारी तकनीकें जिनका आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी के कारण उपयोग कर पा रहे हैं, वे खत्म हो जाएगी. इनमें जीपीएस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मौसम निगरानी, और यहां तक कि अंतरिक्ष अनुसंधान तक पर बहुत बुरा असर पड़ेगा. ये हालात कितने भी काल्पनिक हो, लेकिन इनका खतरा और जोखिम बढ़ रहा है. और अभी तो तेजी से हजारों सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च होने वाले है. इन्हें रोकना नामुमकिन है. अगर जल्दी ही समाधान नहीं निकला तो पृथ्वी की कक्षा उपयोग के लायक ही नहीं रह जाएगी.

क्या क्या होगा इस कचरे में?

स्पेस डेबरी या स्पेस जंक में बहुत कुछ आता है. इसमें खत्म हो चुके सारे सैटेलाइट, इंसानों का छोड़ गया कचरा, रॉकेट के वे हिस्से जो पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं जा पाए है, बेकार हो चुके अंतरिक्ष यान और उन सबके टूट चुके टुकड़े शामिल है. यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मुताबिक, 1950 से करीब 50 हजार टन का पदार्थ स्पेस में लॉन्च किया जा चुका है और सितंबर 2025 तक 13 हजार टन का सामान कक्षा में ही पड़ा है. अब तक लॉन्च किए गए 19590 सैलेटलाइट में से 13230 अब भी कक्षा में है और इनमें से 10200 फिलहाल काम कर रहे है.

एक इंच का कचरा भी तबाही के लिए काफी

परेशानी ये है कि एक इंच का कचरा भी हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कक्षा में घूमता है और वह एक स्पेस स्टेशन से टकरा कर उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए काफी होता है. ऐसी घटना से बचने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कई बार अपनी स्थिति बदलनी पड़ी है. ऐसा लगभग सभी सैटेलाइट करते ही रहते है.

साफ कैसे होगा ये कचरा?

साफ है कि केसलर सिंड्रोम के हालात बनने से पहले ही स्थिति से निपटने के तरीके खोजने होंगे और समाधान खोज कर समस्या का हल निकालना होगा. इस कचरे को साफ करने के लिए कई तरह की रिसर्च चल रही है. इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सुझाव है कि हर कंपनी को उसके सैटेलाइट के 25 साल पूरे करने के बाद उसके कचरे को खुद ही हटाना होगा. वहीं निजी कंपनियां इसमें व्यवसाय की संभावनाएं देख कई सुझावों के साथ आगे आई है. पर सबसे बड़ी चुनौती उपायों को लागू कर उनका नियमन होगा

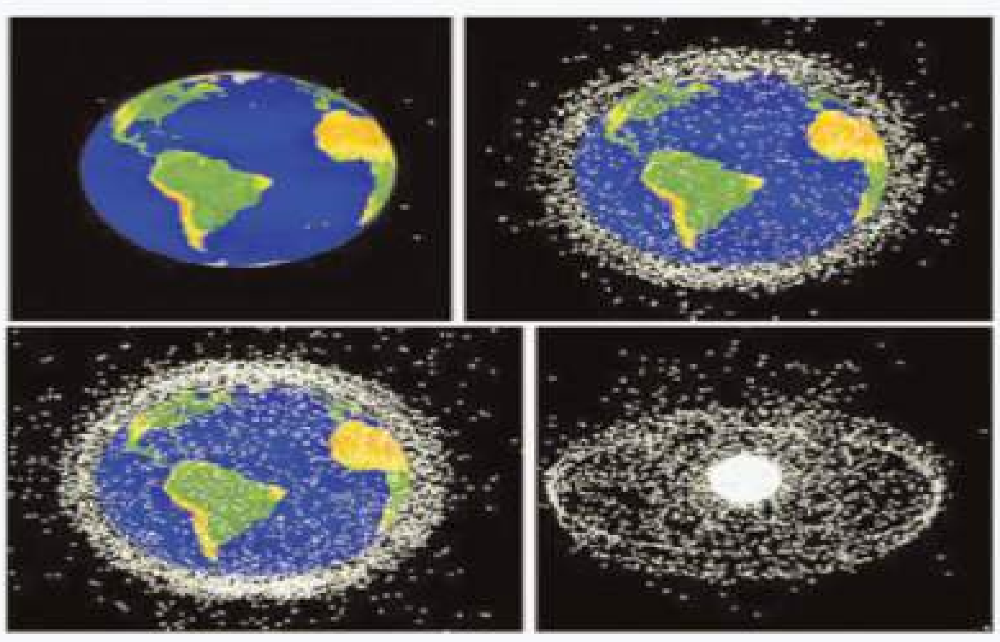

क्या आपको पता है पुलिस का फुल फॉर्म?

पुलिस ये एक ऐसा शब्द है, जिससे हे व्यक्ति अपने बचपन से ही परिचित होता है। सभी जानते है कि देश के किसी भी क्षेत्र में होने वाले अपराधों से निपटने में पुलिस अहम भूमिका निभाती है और सुरक्षित समाज के निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साबित होती है। पुलिस के कर्तव्यों और उनसे मिलने वाली मदद से तो लगभग हर कोई परिचित है लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाकी पदों की तरह आखिर पुलिस का फुल फॉर्म क्या होता है। जाहिर सी बात है बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी।

सुरक्षित समाज की निर्माता

पुलिस एक ऐसा सुरक्षा बल है, जो देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर पल डटकर खड़ा रहता है। जिस तरह से सेना देश की सीमा पर खड़े होकर बाहरी दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है। ठीक उसी तरह से आंतरिक क्षेत्र में मौजूद अनैतिक गतिविधियों से निपटकर, अपराधियों को पकड़ कर समाज और लोगों की रक्षा करती है।

सितारे दर्शाते हैं पद

पुलिस में महिला और पुरुषों दोनों की ही भर्ती होती है जिन्हें आरक्षी और आरक्षक कहा जाता है। पद के हिसाब से वर्दी पर सितारे अंकित किए जाते हैं। जो ये दर्शाते है कि किस पुलिस अधिकारी के पास विभाग का कौन सा पद है। पुलिस विभाग में कार्यरत कांस्टेबल से लेकर उच्च श्रेणी तक के सभी अधिकारियों का काम देश की आंतरिक सुरक्षा होता है।

जनता की सहायक

पुलिस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को देश की सुरक्षा और कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होता है। देश की कानून व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखना और किसी मामले में परेशान व्यक्ति की मदद करना पुलिस का मुख्य काम है और कोई भी इनसे मदद ले सकता है। किसी भी समस्या से परेशान चल रहा व्यक्ति अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है।

पुलिस का पूरा नाम

भारत में पुलिस विभाग की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा की गई थी और उसके बाद से आज तक यह देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख अंग है। पुलिस का फुल फॉर्म पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसी होता है। नाम से ही जाहिर है कि ये सुरक्षा बल जनता की सहायता के लिए काम करता है।

दुनिया का सबसे बड़ा आइस फेस्टिवल है हार्बिन इंटरनेशनल स्नो फेस्टिवल

हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल, चीन के हार्बिन शहर में हर साल जनवरी से फरवरी के अंत तक आयोजित किया जाता है. यह दुनिया का सबसे बड़ा आइस फेस्टिवल है. यह फेस्टिवल करीब एक महीने तक चलता है. इस फेस्टिवल में बर्फ से बनी कलाकृतियां बनाई जाती है. हर साल एक थीम के साथ यह फेस्टिवल मनाया जाता है. इस फेस्टिवल में 12 देशों के कलाकार हिस्सा लेते हैं. हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल की शुरुआत 1985 में की गई थी। हार्बिन चीनी भाषा का शब्द है। जिसका शाब्दिक अर्थ वह जगह जहां मछलियों को पकड़ने वाला जाल सुखाया जाता है।

चीन के हेइलोंगजियांग प्रांत में होने वाला हार्बिन आइस फेस्टिवल दुनियाभर में बर्फ की सबसे बड़ी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। इस फेस्ट में बर्फ से न केवल मूर्तियां आदि बनाई जाती है, बल्कि बर्फ से महल यहां तक की पूरा ड्रीम वर्ल्ड बनाया जा चुका है। सोमवार को आइस एंड स्नो वर्ल्ड को ट्रायल के लिए खोला गया, जिसमें बर्फ से बनी कलाकृतियों को रंग बिरंगी रोशनियां डालकर सजाया गया था। हार्बिन शहर में पड़ने वाली जबरदस्त बर्फ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन यहां हार्बिन आइस फेस्टिवल का आयोजन करता है। फेस्टिवल में आइस एंड स्नो वर्ल्ड, आर्ट एंड स्नो आर्ट एग्जीबिशन, आइस लैंटर्न आर्ट फेयर, विंटर स्वीमिंग, आइस होटल, स्कीइंग और स्लेज जैसे कई आकर्षण है। इस फेस्ट की गिनती दुनिया के सबसे बड़े स्नो फेस्ट में होती है। हर साल इस बर्फीली दुनिया को देखने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग आते है। हाड़ कंपा देने वाली ठंड में चीन में लगने वाला स्नो वर्ल्ड पार्क खुल गया है। -20 डिग्री तापमान में 2000 कलाकारों ने बर्फ से बनी कलाकृतियां बनाई है। इन कलाकारों ने दिन रात मेहनत कर इस अनोखी कलाकृतियों को बनाया है। हर साल चीन के हेइलोंगजियांग प्रांत के हार्बिन शहर में बर्फ से बनी कलाकृतियों का आइस एंड स्नो वर्ल्ड का आयोजन किया जाता है। यह फेस्ट दो महीने तक चलेगा और यह विश्व का अपनी तरह का इकलौता पार्क है। यह उत्सव फरवरी के आखिर तक चलेगा। इस सालाना उत्सव में न सिर्फ चीन के लोग बल्कि दुनियाभर के पर्यटक इस फ्रोजन सिटी आते है और बर्फ की बनी कलाकृतियों का आनंद लेते है।

यह पूरा पार्क छह लाख वर्ग मीटर में फैला है इसलिए इसे स्नो वर्ल्ड भी कहते है। इस पार्क में अपनी कला का जलवा दिखाने देश-विदेश के कलाकार भाग लेते है। बता दें कि हेइलोंगजियांग प्रांत काफी ठंडा है।

हर साल इसकी प्रसिद्धी को देखते हुए इसका फेस्टिवल का आकार प्रकार बड़ा होता जा रहा है। पिछले साल यह पार्क 8 लाख वर्ग मीटर में बनाया गया था, जिसमें 1.5 लाख घन मीटर बर्फ उपयोग की गई थी। यह बर्फ 2023 की तुलना में 30 हजार घन मीटर अधिक उपयोग की गई थी। पार्क में स्कल्पचर बनाने में 1.8 लाख बर्फ के क्यूब का इस्तेमाल हुआ था। बता दें कि यह फेस्टिवल करीब 35 साल से आयोजित किया जा रहा है और इसे देखने हर दिन करीब एक लाख से अधिक लोग आते है। इन अजूबों को चीन और दुनियाभर के 12 देशों से पहुंचे 10 हजार कलाकारों ने बनाया है, वह भी बर्फ में माइनस 10 से माइनस 20 डिग्री तापमान के बीच। हर साल दिसंबर के वक्त तापमान काफी नीचे गिर जाता है। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक, शहर के एयरपोर्ट पर 2025 में दो करोड़ से ज्यादा यात्री आए। पर्यटकों के बीच हार्बिन में बना साइबेरियन टाइगर पार्क भी लोकप्रिय है। यहां एक हजार से ज्यादा साइबेरियाई टाइगरों को ठंडे पर्यावरण के बीच सुरक्षित माहौल में रखा गया है।

बर्फ की मूर्तियों के अलावा, यहाँ अन्य गतिविधियां भी होती है। इसमें सर्दियों में होने वाली तैराकी, बर्फ बोटिंग के साथ-साथ बर्फ पर होने वाला सामूहिक विवाह समारोह भी शामिल है। यहां दुनिया भर से लोग शादी करने पहुंचते हैं।

कलिंग समाचार

संपादकीय

बुधवार 28 जनवरी 2026

इतिहास, संस्कृति और धर्म से खिलवाड़

नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तेजी से अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जमीन राम मंदिर बनाने के लिए दे दी गई और फिर वहां राम मंदिर बन भी गया, उससे भाजपा समर्थकों में यह विश्वास और पु ता हो गया कि मोदी के रहते हिंदू धर्म सुरक्षित रहेगा और हिंदू जागा रहेगा। हालांकि हिंदू कब सोया हुआ था और धर्म को कब खतरा था, इसका कोई तार्किक जवाब इन समर्थकों के पास नहीं है। क्यों धर्म खतरे में रहता तो देश में हिंदू आबादी बहुसं यक नहीं रहती। बहरहाल, भाजपा की धर्म की राजनीति में आम जनता की आस्था उलझ कर रह गई और अब जब धर्म का तरह–तरह से अपमान हो रहा है, तो यह उलझी हुई धार्मिक जनता समझ नहीं पा रही है कि उसे क्या करना चाहिए। अभी तीन–चार तीन पहले नरेन्द्र मोदी शिवजी की तरह डमरू बजाते दिखे, इसके बाद पतंगबाजी का शौक पूरा करने के लिए हनुमानजी को ही पतंग की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन हिंदू सोया रहा, उसे अपने आराध्य भगवानों के अपमान पर आपत्ति नहीं हुई। उत्तरप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने हनुमानजी के अपमान के विरोध में लखनऊ में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहा, तो पुलिस ने उन्हें रोका। हालांकि पाठ फिर भी उन्होंने पूरा किया। लेकिन इसमें कोई हिंदुत्ववादी संगठन अजय राय का साथ देने आगे नहीं आया। जो लोग चर्च या मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उन्हें इस बात से तकलीफ नहीं हुई कि मंदिर में किसी को हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्यों रोका जा रहा है। धर्म को लेकर यह दोहरा रवैया जाहिर करता है कि भाजपा के लिए धर्म केवल राजनीति में सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आस्था पर पैर रखकर अपमानित करने से भाजपा नेताओं को कोई गुरेज नहीं है। इसी तरह प्राचीन संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों का भी लगातार तिरस्कार भाजपा कर रही है। अभी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के हजार साल मनाए गए और नरेन्द्र मोदी ने इसमें कहा कि यह हमारी विजय का प्रतीक है, क्योंकि आक्रमण के बाद भी सोमनाथ को नष्ट नहीं किया जा सका। लेकिन खुद मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मंदिरों, मूर्तियों और घाटों को जीर्णोद्धार के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है। इसमें मणिकर्णिका घाट को भी नहीं ब शा गया, जो हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र श्मशान घाटों में से एक है। मोक्ष की कामना में श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन शायद नरेन्द्र मोदी की नजर में श्रद्धा का कोई मोल नहीं है, उन्हें केवल मुनाफे की भाषा समझ आती है। तभी तो इस पवित्र माने जाने वाले घाट का अविचारित पुनरूद्धार किया जा रहा है। जिसमें पुराने घाटों और मूर्तियों पर बेरहमी से बुलडोजर चला दिया गया और जब इसका विरोध शुरु हुआ तो जिला प्रशासन का जवाब आया कि मूर्तियों को दोबारा लगाने के लिए सुरक्षित रखा गया है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि दीवारों में लगी कुछ कलाकृतियां व मूर्तियां प्रभावित हुई हैं लेकिन उन्हें संस्कृति विभाग द्वारा सुरक्षित कर लिया गया है और काम पूरा होने के बाद उन्हें उनके मूलरूप में फिर से स्थापित किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस तरह के कामों में पहले से सावधानी क्यों नहीं बरती गई। जब मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया था, तब भी कई पुरानी मूर्तियां और छोटे मंदिरों को तोड़ा गया था। अब अहिल्याबाई होलकर की लगभग सौ साल पुरानी मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। जबकि इन्हीं देवी अहिल्याबाई होलकर ने मणिकर्णिका घाट का निर्माण करवाया था और कई मंदिरों का संरक्षण भी किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को घेरते हुए एक पोस्ट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ ध्यान दिलाया है और अहम सवाल पूछे हैं। उन्होंने लिखा कि %%गुप्त काल में वर्णित जिस मणिकर्णिका घाट का लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने पुनरुद्धार कराया था, उस दुर्लभ प्राचीन धरोहर को आपने पुनरुद्धार के बहाने तुड़वाने का अपराध किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भोंडे सौंदर्यीकरण और व्यवसायीकरण के नाम पर बनारस के मणिकर्णिका घाट में बुलडोजर चलवाकर सदियों पुरानी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को ध्वस्त कराने का काम किया है।

तीस्ता नदी परियोजना पर बांग्लादेश ने भारत के विरुद्ध चीन से मदद मांगी

आशीष विश्वास

बांग्लादेश की मदद करने के लिए विशिष्ट स्थितियों में चीन द्वारा हस्तक्षेप करने की संभावना के बारे मेंए बीजिंग की प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल–परफेक्ट थीए जैसा कि प्रमुख शक्तियों के साथ आम तौर पर होता है। ढाका को बताया गया कि बड़ा देश अपने छोटे क्षेत्रीय पड़ोसियों को व्यापार और व्यवसाय के विकास सहित सभी द्विपक्षीय मामलों में मदद करने के लिए हमेशा तैयार है।

यह कोई रहस्य नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अंतरिम बांग्लादेश सरकार के मु य सलाहकार डॉण् मोह मद यूनुस के बीच कोई खास रिश्ता नहीं है। कुछ हद तक विरोधाभासी रूप सेए दोनों में एक असामान्य विशेषता है.यदि आवश्यक हो तो मौजूदा राजनयिक मानदंडों और परंपराओं को रौंदने का उनका दृढ़ संकल्पए क्योंकि वे कम से कम समय में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से संकेत दिया है कि दक्षिण एशिया से संबंधित मामलों मेंए वह बांग्लादेशी संवेदनाओं के बारे में किसी भी स्पष्ट चिंता के बिना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अधिक निकटता से जुड़ना पसंद करते हैं। ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार से निपटने में आने वाली कठिनाइयों से अनभिज्ञए चालाक डॉण् यूनुस अपने तरीके से पलटवार कर रहे हैंरू 1971 के बाद के पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को फिर से जगाने के बादए बांग्लादेश ने अब चीन को पहले से कहीं ज़्यादा आक्रामक तरीके से लुभाना शुरू कर दिया हैए लेकिन इस दिशा में उसके प्रयासए जैसा कि पहले पाकिस्तान के साथ हुआ थाए निकट भविष्य में महत्वपूर्ण लाभ नहीं ला पाये हैं।

यह देखना मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों है। डेमोक्रेट्स से पहले के समर्थन से कटे हुएए यूनुस के नेतृत्व वाला बांग्लादेशए अमेरिका के वर्तमान पसंदीदा भारत के लिए घर के नज़दीक जितना संभव हो सके उतना मुश्किल बनाकर ट्रंप प्रतिष्ठान को धोखा देना चाहेगा। ढाका के इस कदम से कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश ने अभी तक दक्षिण एशिया में एक संप्रभु तथा स्वतंत्र देश के रूप में काम करने में बहुत प्रगति नहीं की हैए क्योंकि उसे अपने बड़े पड़ोसियों जैसे चीन या भारत से स्पष्ट समर्थन की आवश्यकता रहती है।

बांग्लादेश के लिए संकट यह है कि यूनुस की अन्य योग्यताएं चाहे जो भी होंए मूल रूप से एक अनिर्वाचित पदाधिकारी हैंए जो राजनीतिक प्रतिष्ठा का आनंद ले रहे हैं परन्तु अत्यधिक जटिल दक्षिण एशियाई राजनीतिक खदानों से गुजरते हुए कूटनीतिक रूप से अभद्र साबित हो रहे हैं। उनकी दुर्दशा पर विचार करेंरू इस व्यक्ति को एक हिंसक त तापलट के माध्यम से सत्ता में लाया गया हैए जिसकी वजह से 5 अगस्त 2024 से बांग्लादेश में 2000 लोगों की जानें जा चुकी हैं ;और यह सं या अभी भी बढ़ रही है!द्ध। उनके मु य घरेलू समर्थकों मेंए कट्टरपंथी जमातीध्इस्लामी चरमपंथी सुर में सुर मिलाते हैंए यहां तक कि शक्तिशाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ;बीएनपीद्ध को भी दरकिनार कर देते हैंए जो चुनावों के माध्यम से वैध रूप से अर्जित राजनीतिक सत्ता का प्रमुख दावेदार है। ढाका से भारत के खिलाफ़ शुरुआती धमकियांए जिनमें पाकिस्तान या चीन से उधार लिये गये परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके या संकीर्ण सिलीगुड़ी गलियारे को काट कर परमाणु हमला करने की कुछ विचित्र ;और हास्यास्पद!द्ध कल्पनाएं शामिल थींए जो इस्लामी चरमपंथियों के दबाव में की गयी थीं।

गौरतलब है कि बीएनपी ने शुरू में यूनुस का समर्थन करने के बावजूद कभी भी खुद को इस तरह की मूर्खतापूर्ण कॉल और चेतावनियों से नहीं जोड़ा। बहुत देर सेए महान मु य सलाहकार को एहसास हुआ कि उन्हें गलत सलाह दी जा रही थीए अगर वास्तव में स्वदेशी कट्टरपंथी इस्लामी उग्रवादियों की भीड़ द्वारा उन्हें गुमराह नहीं किया जा रहा था तो। इन लोगों ने पाकिस्तानए सिंगापुरए थाईलैंडए मलेशियाए मध्य पूर्व और अन्य देशों से सब्जियांए चावल और चीनी आयात करने की कोशिश कीए और भारत का पूरी तरह से बहिष्कार किया!

यह हताशा की हद है कि ढाका ने तीस्ता जल बंटवारे के मुद्दे पर एक सावधानीपूर्वक नियंत्रित भारत विरोधी आंदोलन को प्रायोजित करने की कोशिश की है। यह कदम टीम यूनुस को बहुत जरूरी समय देगा और वर्तमान शासकों और उनके सलाहकारों के खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश को अस्थायी रूप से कम करेगा। तीस्ता नदी को बचाने के तरीके के बारे में चीन के साथ बातचीत फिर से शुरू हो गयी है। ढाका स्थित राजनयिकों के बीच वार्ता में इस परियोजना को पुनर्जीवित किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार चीन द्वारा अंतरिम शासकों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने की संभावनाए कम से कम पहले के अमेरिकी समर्थन के नुकसान की भरपाई के लिए चर्चाओं में भी शामिल थी।

सौभाग्य से अंतरिम सरकार ने आखिरी समय में अपना रुख बदल दिया और भारत विरोधी बयानबाजी को कम किया और गुस्साए प्रदर्शनकारियों के बढ़ते दबाव के तहत सीमा व्यापार और भारत से आवश्यक वस्तुओं के आयात को पहले की तरह सामान्य करने की कोशिश की!

ऐसा नहीं है कि यूनुस की टीम के पास ज़्यादा विकल्प थे। बीएनपी ने पहले ही मु य सलाहकार के प्रति अपनी बढ़ती हुई अधीरता के पर्याप्त संकेत दे दिये हैंए जो पिछले छह महीनों के दौरान अपने सभी कदमों के माध्यम से किसी न किसी बहाने से लंबे समय से प्रतीक्षित चुनावों को रोक रहे हैं। देश की दूसरी प्रमुख ताकतए अवामी लीग ;एएलद्धए जिसकी नेता श्रीमती हसीना वाजेद अभी भी निर्वासन से काम कर रही हैंए पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन बीएनपी ने भी इसका विरोध किया है। बांग्लादेश में वैध लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होने के नातेए अनुभवी बीएनपी नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि एएल के बिना आम चुनाव आयोजित करनाए जैसा कि जमात सुनिश्चित करना चाहते हैंए उन्हें घर या विदेश में शायद ही कोई विश्वसनीयता हासिल होगी।

इसके अलावा जमात के नेताओं ने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति के लिए मु य सलाहकार की आलोचना करना शुरू कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हसीना के प्रशासन के तहत उनके देश को परेशान करने वाली सभी बुराइयां . शीर्ष पर भ्रष्टाचारए राज्य प्रायोजित हिंसा और अराजकताए असहमति का बलपूर्वक दमनए लोगों के बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाली उच्च मुद्रास्फीतिए सांप्रदायिक हमलों का लगातार प्रकोप . बेरोकटोक जारी है। एकमात्रउपाय है कि एक बार फिर से आम चुनाव करवाये जायें। अंतरिम सरकार ने अभी तक अपने मु य प्रायोजक की ओर से इस आभासी अभियोग का जवाब नहीं दिया है।

यह हताशा की हद है कि ढाका ने तीस्ता जल बंटवारे के मुद्दे पर एक सावधानीपूर्वक नियंत्रित भारत विरोधी आंदोलन को प्रायोजित करने की कोशिश की है। यह कदम टीम यूनुस को बहुत जरूरी समय देगा और वर्तमान शासकों और उनके श्सलाहकारोंश् के खिलाफबढ़ते जनाक्रोश को अस्थायी रूप से कम करेगा। श्तीस्ता नदी को बचानेश् के तरीके के बारे में चीन के साथ बातचीत फिर से शुरू हो गयी है।

ढाका स्थित राजनयिकों के बीच वार्ता में इस परियोजना को पुनर्जीवित किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसारए चीन द्वारा अंतरिम शासकों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने की संभावनाए कम से कम पहले के अमेरिकी समर्थन के नुकसान की भरपाई के लिएए चर्चाओं में भी शामिल थी।

चीन के साथ गुप्त कूटनीतिक पहल के परिणामस्वरूप अब तक चीन की ओर से एक विशिष्ट प्रोटोकॉल.अनुमोदित प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजिंग हलकों ने बताया कि नदी विशेषज्ञों ने दो साल के लंबे अध्ययन और सर्वेक्षण के बाद तीस्ता नदी को पुनर्जीवित करने की प्रस्तावित बांग्लादेश योजना के जवाब में पहले ही अपने सुझाव दे दिये हैं। यह बांग्लादेश को बताना था कि क्या वह इस परियोजना पर आगे बढ़ना चाहता हैए जिसके लिए चीन आवश्यक होने पर धन देने के लिए तैयार है। इसके अलावाए पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर दोनों देश आधिकारिक समझौते के बाद ढाका द्वारा अपने बड़े उत्तरी पड़ोसी से पहले की तरह अधिक हथियार और गोला.बारूद खरीदने पर भी चर्चा शुरू कर सकते हैं।

हालांकि बांग्लादेश की मदद करने के लिए विशिष्ट स्थितियों में चीन द्वारा हस्तक्षेप करने की संभावना के बारे मेंए बीजिंग की प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल.परफेक्ट थीए जैसा कि प्रमुख शक्तियों के साथ आम तौर पर होता है। ढाका को बताया गया कि बड़ा देश अपने छोटे क्षेत्रीय पड़ोसियों को व्यापार और व्यवसाय के विकास सहित सभी द्विपक्षीय मामलों में मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन बीजिंग सभी देशों के साथ समान संप्रभु साझेदार के रूप में व्यवहार करने में विश्वास करता हैए इसलिए चीनियों को भरोसा था कि परिपक्व घरेलू राजनीतिक प्रतिष्ठान और साथ ही बांग्लादेश के लोकतंत्र.प्रेमी लोगए घर और विदेश दोनों में अपनी समस्याओं से निपटने और उन्हें सुलझाने में पूरी तरह सक्षम हैं।

अगर बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों के लहजे पर गौर करेंए तो चीन के ऐसे अच्छेए सुकून देने वाले शब्दों की आधिकारिक तौर पर सराहना की गयी। हालांकिए अंतरिम सरकार के लिए ये शब्द बहुत कम राहत लेकर आयेए जो अभी भी नयी ट्र प टीम की कड़ी आलोचना से परेशान है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंडराता संकट–बढ़ता कर्ज, सरकारी संरक्षणवाद और पूंजीवादी मिलीभगत

सचिन श्रीवास्तव

सरकार एक ओर निजीकरण और विनिवेश के नाम पर सार्वजनिक संपत्तियों को बेचना चाहती हैए जबकि दूसरी ओर कृषि जैसे बुनियादी क्षेत्रों को बड़े औद्योगिक घरानों के हवाले करने की कोशिश कर रही है। यह नीतियां न केवल आम जनता के लिए आर्थिक असुरक्षा पैदा कर रही हैंए बल्कि देश की प्रतिस्पर्धी क्षमता को भी कमजोर कर रही हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय गहरे संकट में है। सरकार के नीति.निर्माण में असंतुलनए कर्ज का बढ़ता बोझ और सरकारी संरक्षित पूंजीवाद ;क्रोनी कैपिटलिज़्मद्ध के कारण प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भरता दोनों प्रभावित हो रहे हैं। 80 प्रतिशत से अधिक जीडीपी के बराबर कर्ज और नीति निर्माण में बड़े कॉरपोरेट समूहों की बढ़ती पकड़ ने देश की आर्थिक संप्रभुता को खतरे में डाल दिया है।

सरकार एक ओर निजीकरण और विनिवेश के नाम पर सार्वजनिक संपत्तियों को बेचना चाहती हैए जबकि दूसरी ओर कृषि जैसे बुनियादी क्षेत्रों को बड़े औद्योगिक घरानों के हवाले करने की कोशिश कर रही है। यह नीतियां न केवल आम जनता के लिए आर्थिक असुरक्षा पैदा कर रही हैंए बल्कि देश की प्रतिस्पर्धी क्षमता को भी कमजोर कर रही हैं।

स्टेटिस्टा के अनुसार भारत का राष्ट्रीय कर्ज 2020 में 88ण्43प्रतिशत जीडीपी तक पहुंच गया थाए जो अब भी 80प्रतिशत से अधिक बना हुआ है। सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि अर्थव्यवस्था सुधार की ओर बढ़ रही हैए लेकिन वास्तविकता यह है कि सरकारी नीतियां कुछ विशेष औद्योगिक समूहों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैंए न कि आम जनता या लघु.मध्यम उद्यमों ;एमएसएमईद्ध के हित में।

सरकारी बैंक और कंपनियां घाटे में बताकर बेची जा रही हैंए लेकिन उन्हें खरीदने वाले उद्योगपतियों को सस्ते ऋण और टैक्स में छूट दी जा रही है। रेलवेए तेल कंपनियांए टेलीकॉम और एयरपोर्ट जैसे बुनियादी ढांचे को कुछ खास समूहों के हाथों बेचा जा रहा हैए जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म हो रही है। छोटे व्यापारियों और किसानों को बाजार के भरोसे छोड़ दिया गयाए जबकि बड़े उद्योगपतियों को अरबों की टैक्स रियायतें दी जा रही हैं। सरकार बार.बार कहती है कि सार्वजनिक उपक्रम घाटे में हैंए लेकिन क्या सच में ऐसा हैघ् भारत पेट्रोलियमए जीवन बीमा निगमए रेलवेए इस्पात प्राधिकरण और अन्य कंपनियों को या तो बेचा जा रहा है या उनके संसाधन निजी हाथों में दिये जा रहे हैं। सरकारी संपत्तियों की बिक्री से जो पैसा आ रहा हैए वह मौजूदा कर्ज चुकाने में नहींए बल्कि नए कॉर्पोरेट टैक्स छूट और सरकारी खर्च बढ़ाने में इस्तेमाल हो रहा है। बाज़ार में प्रतिस्पर्धा खत्म हो रही हैए क्योंकि सरकारी संरक्षण प्राप्त निजी कंपनियां मनमाने दाम वसूल रही हैं। सवाल वही है कि यह निजीकरण की नीति है या बस बड़े कॉरपोरेट समूहों को फायदा पहुंचाने का तरीकाघ्

तीन कृषि कानूनों को जबरदस्ती लागू करने की कोशिश सरकार की नवउदारवादी सोच और पूंजीपतियों की लॉबी का स्पष्ट प्रमाण थी। ये कानून किसान आंदोलन के दबाव में वापस लिए गएए लेकिन सरकार अब भी कृषि सेक्टर में बड़े उद्योगपतियों को प्रवेश दिलाने की कोशिश कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी नहीं दी जा रहीए ताकि किसान मजबूरी में निजी कंपनियों को अपनी उपज बेचें। कृषि को ठेकेदारी खेती के हवाले करने की योजनाएं अब भी जारी हैंए जिससे छोटे किसान बिचौलियों और बड़ी कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे। सरकार ने स्नष्टद्ध का बजट लगातार घटाया हैए जिससे सरकारी खरीद कमज़ोर हुई और किसान खुले बाजार में जाने को मजबूर हुए।

खाद्य सुरक्षा पर खतरारू अगर कृषि उत्पादन पूरी तरह बाजार के हाथ में आ गयाए तो खाद्य पदार्थों की कीमतें निजी कंपनियां तय करेंगीए जिससे गरीबों के लिए अनाज महंगा हो जाएगा। छोटे किसानों की बर्बादीरू भारत में 86प्रतिशत से अधिक किसान लघु या सीमांत श्रेणी के हैं। बड़े कॉरपोरेट के साथ प्रतिस्पर्धा में वे टिक नहीं पाएंगे।भूमि अधिग्रहण और विस्थापनरू कॉरपोरेट खेती के बढ़ने से गांवों में जमीनें उद्योगपतियों के हाथों में जाएंगीए जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी।

अगर सरकार सच में किसानों का भला चाहती हैए तो उसे. रूस्क्र की कानूनी गारंटी देनी होगी। स्नष्टद्ध को मजबूत करना होगाए ताकि सरकारी खरीद में कोई गिरावट न हो।कृषि आधारित छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना होगाए जिससे किसान आत्मनिर्भर बनें। सच्चे प्रतिस्पर्धी बाजार का अर्थ है कि कोई भी नया व्यवसायी बिना किसी भेदभाव के बाजार में प्रवेश कर सके और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिले। लेकिन भारत में सरकार खुद ही कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को बाज़ार पर कब्जा करने में मदद कर रही है। टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ दो.तीन कंपनियां ही बची हैंए क्योंकि अन्य कंपनियों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया गया। एयरपोर्टए हाईवेए रेलवेए बिजली उत्पादन और शिपिंग जैसे क्षेत्रों में एकाधिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। बैंकों से कर्ज माफ़ी और टैक्स छूट केवल कुछ बड़े व्यापारिक समूहों को दी जाती हैए जबकि छोटे व्यापारियों को लोन भी नहीं मिलता।इसका खतरा क्या है? महंगाई बढ़ेगीए क्योंकि कम प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियां मनमाने दाम वसूलेंगी।

नये कारोबार शुरू करना मुश्किल होगाए क्योंकि नये व्यवसायियों को बड़े कॉरपोरेट के साथ मुकाबला करना असंभव होगा।रोज़गार कम होंगेए क्योंकि बड़े औद्योगिक समूह मशीनों और स्वचालन ;ऑटोमेशनद्ध पर निर्भर रहेंगेए जिससे नौकरियां घटेंगी। सरकार अगर सच में मुक्त बाज़ार और प्रतिस्पर्धा चाहती हैए तो उसे छोटे और मध्यम व्यापारियों को भी समान अवसर देने होंगे। एकाधिकारवाद को खत्म करने के लिए नियम और कानून स त करने होंगे। सरकारी बैंकों को सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए इस्तेमाल करने की नीति बंद करनी होगी।

भारत की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में हैए लेकिन इस संकट का कारण कोई प्राकृतिक आपदा नहींए बल्कि सरकारी नीतियां और कॉरपोरेट संरक्षणवाद है। सरकार जिन सुधारों की बात कर रही हैए वे वास्तव में सिर्फ कुछ गिने.चुने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाये गये हैं।

निजीकरण का विरोध किया जाना चाहिएए क्योंकि यह सार्वजनिक संसाधनों की लूट है। कृषि क्षेत्र में बड़े कॉरपोरेट्स की घुसपैठ को रोका जाना चाहिएए ताकि किसान बिचौलियों का शिकार न बनें। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए बड़े उद्योगपतियों को मिलने वाली सरकारी रियायतों को खत्म किया जाना चाहिये।आज सवाल यह नहीं है कि भारत आर्थिक संकट से बाहर कैसे निकलेगाए बल्कि सवाल यह है कि क्या सरकार सच में आम जनता की भलाई चाहती हैए या सिर्फ अपने प्रिय उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है?

विविध समाचार

सदर अस्पताल में ऑपरेशन से मिला नया जीवन

रांची २७/०१ (संवाददाता): सदर अस्पताल में पहली बार पीडियाट्रिक सर्जरी हुई। 8 माह के बच्चे विनय के पेशाब के रास्ते में परेशानी थीए ज्योंकि स्किन सटा हुआ था। उसे पेशाब करने में काफी परेशानी होती थी। ज्यादा जोर लगाने पर कभी.कभी पेशाब के रास्ते खून आने लगता था।

दर्द की वजह से उसे हमेशा बुखार हो जाता था। परिजन बच्चे को लेकर सदर अस्पताल पहुंचेए जहां पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में डॉ इमरान ने बच्चे की जांच की। जांच में पता चला कि बच्चे की सर्कमसीजन के बाद लिंग की झिल्ली को चमड़े से अलग करना होगा।

उन्होंने मंगलवार को सर्जरी कर झिल्ली को स्किन से अलग कर दिया। ऑपरेशन के बाद बच्चे को राहत मिली और उसे छुट्टी भी दे दी गई।डॉ इमरान उन दो डॉज़्टरों में से एक हैंए जिनसे अस्पताल प्रबंधन ने एक महीने पहले पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए एमओयू किया था। दैनिक भास्कर ने 25 मई के अंक में खबर छापी थी कि एक जून से सदर अस्पताल में छोटे बच्चों की जटिल सर्जरी शुरू हो जाएगी। डॉ इमरान ने बताया.समय पर ऑपरेशन नहीं किया जाताए तो खराब हो सकती थीं किडनियां

डॉ इमरान ने बताया कि बच्चे को पेशाब यूरिन करने में हो रही समस्या से जल्द निजात

नहीं दिलाया जाताए तो उसकी किडनियां खराब हो सकती थीं। ज्योंकि यूरिन के लिए जोर लगाने के कारण बैक प्रेशर से इंफेज़्शन का खतरा था। इंफेज़्शन किडनी तक फैल सकता था। उन्होंने बताया कि यूरिन इंफेज़्शन के कारण बुखार और हाईजिन की समस्या हो जाती थी।

डॉ इमरान ने बताया कि आठ माह के सामान्य बच्चे का वजन कम से कम 9 से 10 किलो होना चाहिए। लेकिन विनय का वजन मात्र 4 किलो है। यूरिन न होने और बार.बार बुखार आने से उसका शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा था। बच्चे का ऑपरेशन आयुष्मान भारत योजना के तहत बिल्कुल निरूशुल्क किया गया। प्राइवेट अस्पताल में सिर्फ ऑपरेशन शुल्क के रूप में 40.50 हजार खर्च करने पड़ सकते थे।

पीडियाट्रिक सर्जरी के साथ सुपरस्पेशियलिटी यूरोलॉजी के लिए भी तीन चिकित्सकों से अस्पताल प्रबंधन का करार हुआ था। सप्ताह में हर तीसरे दिन एक.एक यूरोलॉजिस्ट ओपीडी में सेवा दे रहे हैं। यूरोलॉजी सर्जरी के लिए नई मशीनें लगाई जा रही हैं।

पाकुड़ में पुलिस ने 5 वाहनों में भरा माल किया जज़्त

पाकुड़ २७/०१ (संवाददाता):अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पाकुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हिरणपुर थाना पुलिस ने रविवार की देर रात दो स्थानों पर छापेमारी कर 5 वाहनों में भरे कोयले को जज़्त कर लिया है। पुलिस को देखते ही सभी ट्रैज़्टर चालक भाग निकले। कोयला तस्करों ने वाहनों में पहले कोयला भर दिया था। इसे छिपाने के लिए कोयले के ऊपर बालू भर दिया गया था। इससे सामान्य तौर पर यह समझ में नहीं आ रहा था कि वाहनों मे बालू के नीचे कोयला छिपाकर रखा गया था। पुलिस इन वाहन मालिकों का पता लगाने में जुटी है। इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।

हिरणपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार ने सोमवार को मीडिया को बताया कि गुप्त

सूचना मिली थी कि तीन ट्रैज़्टर में कोयला लोड कर चालक डांगापाड़ा.मोहनपुर के रास्ते बंगाल की ओर जाने जाने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मोहनपुर मोड़ के पास पहुंची। पुलिस ने देखा कि डांगापाड़ा की ओर से तीन ट्रैज़्टर आ रहे हैं। चालकों ने दूर से पुलिस को देख लिया। मोड़ पहुंचने के पूर्व ही सभी चालक वाहन छोड़कर भाग निकले।

पुलिस ने जब ट्रैज़्टरों की तलाशी ली तो देखा कि सभी ट्रैज़्टर में कोयला भरा है। उसके ऊपर बालू लोड किया गया है। पुलिस ने तीनों ट्रैज़्टरों को जज़्त कर लिया। इसके बाद पुलिस को पता चला कि कोटालपोखर.हिरणपुर सीमा के पास कोयला डंप कर रखा गया है। पुलिस ने चौड़ा मोड़ के निकट छापेमारी कर डंप कोयला को जज़्त कर लिया। थाना प्रभारी के अनुसार डंप कोयले को दो ट्रैज़्टर में लोड कर थाने लाया गया। पुलिस इस धंधे से जुड़े लोगों का पता लगा रही है। इसके बाद उनपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

राज्य विस्थापन आयोग का होगा गठन, झारखंड कैबिनेट से कुल 67 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

रांची २७/०१ (संवाददाता): झारखंड में विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग के गठन को लेकर प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आयोग में एक अध्यक्ष, दो सदस्य और तीन आमंत्रित सदस्य होंगे। सभी का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। आयोग के गठन को लेकर बनी नियमावली के अनुसार इसका मुज़्य काम विस्थापित परिवारों का सामाजिक आर्थिक अध्ययन कराना होगा।

इस अध्ययन के अनुरूप सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों के पुनर्वास को लेकर आयोग योजनाएं बनाएगा। मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में आयोग के गठन के साथ-साथ कुल 67 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन को ले इसके लिए बनी नियमावली के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर दी गई ।प्रारूप के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, दो सदस्य एवं तीन आमंत्रित सदस्य हो सकते हैं। अध्यक्ष का मनोनयन राज्य सरकार करेगी और इसके लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों अथवा विस्थापन एवं पुनर्वास क्षेत्र में न्यूनतम दस वर्षों का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।

इनके अलावा प्रशासनिक अनुभव रखने वाले अधिकारी को सदस्य बनाया जाएगा, जो संयुक्त सचिव से ऊपर के पदों का कार्य अनुभव रखता होगा।इसके साथ ही सेवानिवृज़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा 40 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ता को सदस्य बनाया जा सकेगा। आमंत्रित सदस्यों में स्थानीय पुरुष अथवा महिला शामिल होंगे। इनका पद अवैतनिक होगा। सरकार उप सचिव से वरीय पदों पर काम करने का अनुभव रखने वाले किसी सरकारी अधिकारी को सदस्य सचिव के तौर पर मनोनीत करेगी।सभी का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा और इन्हें अपना पद त्यागने अथवा इस्तीफा देने के लिए एक माह पूर्व सरकार को सूचित करना होगा।

आयोग पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होगा।रांची में मोरहाबादी मैदान के निकट स्थित पूर्व मुज़्यमंत्री शिबू सोरेन का आवास उनकी पत्नी रूपी सोरेन के नाम पर आवंटित होगा।नगर विकास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जिसे सर्वसज़्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी गई।कहा गया कि इस आवास के कोने-कोने में शिबू सोरेन की यादें बसी हुई हैं। उनके व्यक्तिगत इस्तेमाल की चीजें भी आवास में मौजूद हैं जिनका संरक्षण और देखरेख जरूरी है। भवन निर्माण एवं आवास विभाग को इसके लिए प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

झारखंड मुज़्यमंत्री मंइयां सज़्मान योजना के क्रियान्वयन में आवेदन के समय आवेदिका का लाइव फोटो लेने की अनिवार्यता को क्षांत करने की घटनोज़र स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य ललित कला अकादमी के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई।

इसका उद्देश्य ललित कला और अनुप्रयुक्त कलाओं के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना है। झारखंड प्रयुक्त विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के बीच साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और इनके समग्र विकास के लिए झारखंड राज्य साहित्य अकादमी के गठन की स्वीकृति दी गई। झारखंड में संगीत नाटक और अनुप्रयुक्त कलाओं के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी के गठन की स्वीकृति दी गई।

झारखंड के देवघर-हजारीबाग में 2 शव मिले

हजारीबाग २७/०१ (संवाददाता): झारखंड के देवघर और हजारीबाग में 2 शव बरामद किए गए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर दोनों जिलों में अलग.अलग जगहों से लाश निकाली गई है। हजारीबाग के चौपारण में ळज् रोड सांझा कट के पास झाड़ियों में युवक का शव मिला है वहीं देवघर के बसमता तालाब से एक शव निकाला गया है। पुलिस ने दोनों मामलों में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है।

हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड मुज़्यालय से 10 ज़िड दूर ळज् रोड दनुआ घाटी के ग्राम महानेटांड़ के समीप सांझा कट के पास झाड़ियों से 30 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया है। शव की पहचान नहीं हो सकी है। लाश दिखने की सूचना पर थाना प्रभारी स्वपन कुमार महतो मौके पर पहुंचे। हथिया बाबा मंदिर के पास थोड़ी दूर पर शव मिला। युवक के शरीर पर बस एक जांघिया और दोनों पैर में मौजा था। गर्दन एवं दोनों हाथों में रस्सी के निशान मिले हैं। शव को थाना परिसर में रखा गया है। शनिवार सुबह पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा गया। थाना प्रभारी ने बताया कि ऐसा लगता है कि युवक की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के लिए शव को सुनसान जंगल में फेंक दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

देवघर के नगर थाना क्षेत्र के बसमता मोहल्ले में 40 वर्षीय अधेड़ का शव बसमता तालाब से नगर थाना की पुलिस ने बरामद किया है। मरने वाले की पहचान बसमता मोहल्ले के रहने वाले ललित भूषण मंडल के रूप में की गई है। वह मोहल्ले में ही अपना होटल चलाते थे। पिछले 4 दिनों से लापता थे। परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की शिकायत नगर थाने में दर्ज कराई थी। मृतक के भाई पंकज कुमार मंडल ने बताया कि जमीन विवाद में इसकी हत्या कर शव को छिपाने के उद्देश्य से तालाब में फेंक दिया गया है। शव की सूचना पर सदर ैक़्व् पवन कुमार सहित नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह घटना स्थल पर पहुंचे।

शव का पंचनामा तैयार कराकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया।

6 एई और 6 जेई का कांट्रैज़्ट समाप्त

रांची २७/०१ (संवाददाता):रांची नगर निगम में कांट्रैज़्ट समाप्त होने के बाद भी इंजीनियरों और कंप्यूटर ऑपरेटर से काम लिया जा रहा है। इसका खुलासा मेयर आशा लकड़ा ने किया है। मेयर ने नगर आयुक्त मुकेश कुमार को पत्र लिखकर इस मामले में जवाब भी मांगा है। मेयर ने कहा है कि 4 सहायक अभियंता की सेवा फरवरी 2021ए दो सहायक अभियंता की सेवा मार्च 2021ए 13 कंप्यूटर ऑपरेटर और 9 सहायक डाटा इंट्री ऑपरेटर की सेवा समाप्त हो चुकी है। 6 कनीय अभियंता की सेवा इसी माह समाप्त हो जाएगी। जिनकी सेवा समाप्त हो गईए उन्हें अभी तक सेवा अवधि विस्तार नहीं दिया गया है। इसके बावजूद किस आधार पर उनसे काम लिया जा रहा है और प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है।

झारखंड में शराब की दुकान खोलने को लेकर नया अपडेट, सरकार के कड़े फैसले से कंपनी के फूले हाथ पांव

रांची २७/०१ (संवाददाता): उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में सोमवार को विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सोमवार को 24 शराब कंपनियों के प्रतिनिधियोंए सात प्लेसमेंट एजेंसियों के संचालकों व विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उनकी सर्वाधिक नाराजगी प्लेसमेंट एजेंसियों के विरुद्ध थी।

मंत्री ने सभी प्लेसमेंट एजेंसियों को हिदायत दी है कि एक सप्ताह के भीतर बकाया भुगतान नहीं हुआ तो संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी को काली सूची में डाला जाएगा और उनके विरुद्ध विधि सज़्मत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में ब्रांडेड शराब नहीं मिलने का मामला भी उठा।

मंत्री को कंपनियों के बारे

में बताया गया कि यहां ब्रांड प्रोत्साहित करने का खेल चल रहा है। लोगों को मनचाहा ब्रांड नहीं मिल रहा है। इसपर मंत्री खासे नाराज दिखे। शराब कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनसे मनचाहे ब्रांड की मांग ही नहीं की जाती है। आरोप प्लेसमेंट एजेंसी संचालकों पर था जो किसी खास ब्रांड को प्रोत्साहित करने के लिए उसी ब्रांड की शराब रखे हैं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी जिला मुज़्यालय में एक.दो ऐसी दुकानें होंगीए जिन्हें मॉडल दुकान बनाया जाएगा। अमूमन शराब दुकानों में हर तरह के लोगों की भीड़ रहती हैए जिससे कुछ संभ्रांत परिवार के लोग जाने से हिचकते हैं। मॉडल दुकान होने से वहां अच्छे वर्ग के लोगों को भी बेहतर शराब मिल सकेगी।

शराब दुकानों को भी बेहतर साफसुथरी व बेहतर डिस्प्ले के साथ संचालित करने का निर्देश दिया गया है। अभी अधिकतर दुकानें गोदाम की तरह दिखती हैंए जो सही नहीं है। मंत्री ने बैठक के बाद उत्पाद प्रयोगशाला का भी निरीक्षण किया। यहां तकनीशियन की संज़्या बढ़ाई जाएगी। अवैध शराब की बरामदगी मामले में शराब की भी जांच कराई जाएगी।

नकली या गुणवज़ा पर खरा नहीं उतरने पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। वर्तमान विज़ीय वर्ष में अभी शेष है 1000 करोड़ का लक्ष्य मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि वर्तमान विज़ीय वर्ष में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने 1700 करोड़ का लक्ष्य हासिल किया है। वर्तमान विज़ीय वर्ष में अभी 1000 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना शेष है।

उन्होंने राज्य में भी शराब निर्माण की दिशा में पहल करने को कहा और यह भी कहा कि यहां भी ऐसी कंपनियां बनेंए जिससे शराब का निर्यात हो। इससे लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी।

शराब आपूर्तिकर्ता का भी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इससे राजस्व भी बढ़ेगा। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि कोरोना काल में शराब की बिक्री पर 25 प्रतिशत वैट अलग से लगा था जो अब तक जारी है। इससे शराब की कीमतें अधिक हैं। इसे खत्म किया जाए। .

मंत्री ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में मुज़्यालय स्तर पर एक हाई लेवल टीम बनाई है। इसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। इनके पास एमआरपी से अधिकए ब्रांडेड शराब की उपलज़्धता नहीं होनाए नकली शराब की आपूर्तिए अवैध शराब की आपूर्ति सहित कोई भी शिकायत की जा सकती है।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार

राउरकेला, बुधवार 28 जनवरी 2026

एमसीएल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 77वाँ गणतंत्र दिवस

संबलपुर २७/०१ (संवाददाता): महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने अपने मुख्यालय सहित सभी परिचालन इकाइयों में 77वाँ गणतंत्र दिवस देशभक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया। श्री उदय अनंत काओले, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी), एमसीएल ने कंपनी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा एमसीएल सुरक्षा बल, ओआईएसएफ, एनसीसी, स्काउट्स एवं गाइड्स तथा विद्यालयों के विद्यार्थियों की मार्चिंग टुकड़ियों की सलामी ली। समारोह में एमसीएल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सीएमडी श्री

काओले ने अपने संबोधन में देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोयला कर्मियों के अमूल्य योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं में एमसीएल की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि एमसीएल में साइलो एवं रैपिड लोडिंग सिस्टम के माध्यम से औसत रेक लोडिंग लगभग 42 रेक प्रतिदिन तक पहुँच गई है। उन्होंने सतत खनन पद्धतियों, नवीकरणीय ऊर्जा पहलों तथा सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से सामुदायिक विकास के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता भी दोहराई। इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों में श्री केशव राव, निदेशक (कार्मिक); श्री पी. के. पटेल, मुख्य सतर्कता अधिकारी; श्री ए. के. बेहुरा, निदेशक (वित्त); तथा श्री एस. के. झा, निदेशक (तकनीकी/संचालन/पी एंड पी) शामिल थे।

जागृति महिला मंडल की उपाध्यक्षाएँ भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। समारोह में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष आकर्षण रहा। विजेता प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। इसी प्रकार अंगुल, झारसुगुड़ा एवं सुंदरगढ़ जिलों में स्थित एमसीएल की विभिन्न परिचालन इकाइयों एवं क्षेत्रों में भी गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिससे कर्मचारियों एवं स्थानीय समुदायों के बीच एकता, देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना और अधिक सुदृढ़ हुई।

केंद्रपाड़ा में ज़मीन विवाद में हिंसा, 1 की मौत, 2 घायल

केंद्रपाड़ा २७/०१ (संवाददाता): सदर पुलिस स्टेशन के तहत नरिलो गांव में ज़मीन विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में एक युवक की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान उपेंद्र ओझा के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि यह घटना ज़मीन को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद के परिवार के अंदर शारीरिक हिंसा में बदलने के बाद हुई। जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम को तनाव फिर से बढ़ गया जब राजकिशोर ओझा ने कथित तौर पर अपने भतीजे उपेंद्र से विवाद को लेकर बहस की। यह कहा-सुनी धीरे-धीरे बढ़ गई और आखिरकार हिंसक टकराव में बदल गई। पारिवारिक विवाद के बाद हमला पुलिस सूत्रों ने बताया कि राजकिशोर ओझा ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर कथित तौर पर हथियारों का इस्तेमाल करके उपेंद्र पर हमला किया।

पूर्वतट रेलवे संबलपुर मंडल ने रेलवे स्टेडियम, संबलपुर में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया

संबलपुर २७/०१ (संवाददाता): पूर्व तट रेलवे, संबलपुर मंडल ने रेलवे स्टेडियम, संबलपुर में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया, जहां श्री सुभाष सी चौधरी, मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व तट रेलवे, संबलपुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और रेलवे सुरक्षा बल, एनसीसी, भारत स्काउट्स और गाइड्स की टुकड़ियों से सलामी ली।सभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि संबलपुर मंडल सुरक्षित और कुशल ट्रेन सेवाएं प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, और उन्होंने संबलपुर मंडल के प्रदर्शन को भी रेखांकित किया। अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक मंडल की कमाई 2398.03 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.25 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक 18.17 मिलियन टन माल लदान हुआ, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 9.39त्न अधिक है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बरपाली स्टेशन का आधुनिकीकरण बेहतर संरक्षा और सुविधा के लिए पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए संरक्षा एक शीर्ष प्राथमिकता रही है। इस संबंध में मंडल द्वारा कई उपाय किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप संरक्षा स्तर में काफी सुधार हुआ है। यात्री सुविधाएं हमेशा एक प्रमुख प्राथमिकता रही हैं। संबलपुर मंडल के 14 स्टेशन अब तक सुगम्य भारत मिशन का हिस्सा बनकर 100त्न दिव्यांग अनुकूल हो चुके हैं। 07 स्टेशनों पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म शेड की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर 303 अतिरिक्त बेंच की व्यवस्था की गई है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने रेलकर्मियों से अपने प्रयासों को जारी रखने और अपने कर्तव्य के प्रति मेहनत और समर्पण के साथ काम करने की अपील की ताकि मंडल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके।

इस अवसर पर श्रीमती विंदु चौधरी, अध्यक्ष, पूर्व तट रेल महिला कल्याण संगठन, संबलपुर एवं सदस्य, रेलवे अधिकारी और कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे। श्री पोन्ना वेंकटेश, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी ने इस समारोह का समन्वय किया।

स्कूल में छात्रों के सामने हुई मारपीट के बाद दो महिला टीचर सस्पेंड

संबलपुर २७/०१ (संवाददाता): संबलपुर जिले के बुरला में किरबा प्राइमरी स्कूल के अंदर छात्रों के सामने हुई मारपीट के बाद शिक्षा विभाग ने दो शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद की गई, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया। सस्पेंशन के आदेश धनकौड़ा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी किए।

यह घटना इस महीने को हुई और इसमें दो महिला शिक्षक शामिल थीं, जिनकी पहचान शर्मिष्ठा पल्लाई और कस्तूरी जेना के रूप में हुई है। यह झगड़ा तब सामने आया

जब छात्रों ने कथित तौर पर शिक्षकों के कहने पर अपने मोबाइल फोन पर इस झड़प को रिकॉर्ड कर लिया और बाद में यह फुटेज वायरल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि स्कूल परिसर के अंदर यह विवाद शारीरिक लड़ाई में बदल गया। झड़प के दौरान, कथित तौर पर एक शिक्षक को चोटें आईं और मारपीट के बाद उसके चेहरे से खून बहने लगा।ïद्यह्यश ऋद्बड्डस्र – पीने के पानी की कमी से नाराज ग्रामीणों ने ह॥–57 पर किया प्रदर्शन टॉयलेट की सफाई को लेकर विवाद से हुई झड़प सूत्रों के अनुसार, यह बहस स्कूल के वॉशरूम की सफाई के लिए रखे गए सफाईकर्मी को भुगतान को लेकर असहमति से शुरू हुई थी। जो एक छोटा सा मुद्दा था, वह कथित तौर पर हिंसा में बदल गया, जिससे गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं ज्योंकि यह घटना छात्रों के सामने हुई। सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेश कुमार मिश्रा ने कहा कि वीडियो सामने आने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि जांच जल्द ही पूरी कर ली जाएगी और आगे की कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अधिकारियों ने स्कूलों में अनुशासन पर जोर दिया इस घटना से माता-पिता और स्थानीय निवासियों में चिंता फैल गई है। शिक्षा अधिकारियों ने दोहराया कि स्कूलों में अनुशासन बनाए रखना और सुरक्षित सीखने का माहौल सुनिश्चित करना गैर-समझौता योग्य है, और किसी भी तरह के दुर्व्यवहार से नियमों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।

पीने के पानी की कमी से नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे-57 पर किया प्रदर्शन

संबलपुर २७/०१ (संवाददाता): ओडिशा के नयागढ़ ज़िले के दासपल्ला ब्लॉक के सरिगंडा गांव के लोगों ने सोमवार को अपने इलाके में पीने के पानी की भारी कमी के विरोध में सड़क जाम कर दिया। गांव वालों ने सड़क पर बर्तन और पानी के कंटेनर रखकर खोरधा-बोलंगीर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, जिससे कई घंटों तक गाड़ियों की आवाजाही ठप रही। सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और लंबे समय से चले आ रहे पानी के संकट को हल करने के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ज़िला कलेक्टर और ब्लॉक अधिकारियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों से बार-बार संपर्क करने के बावजूद, अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।गांव वालों के अनुसार, पीने के पानी की कमी एक महीने से ज्यादा समय से बनी हुई है, जिससे परिवारों को रोज़ाना की ज़रूरतों के लिए असुरक्षित

तालाब के पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस स्थिति के स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हुए हैं, खासकर बच्चों और बुज़ुर्गों पर।एक गांव वाले ने बताया कि उन्होंने कई बार ज़िला कलेक्टर और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को सूचित किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा, पिछले एक महीने से हमें सुरक्षित पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ज्योंकि कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए हमारे पास हाईवे जाम करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इसी तरह की चिंता जताते हुए एक स्थानीय महिला ने कहा कि परिवारों को खाना पकाने और पीने के लिए तालाब के पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने कहा, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, फिर भी हमारी समस्याओं को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। गांव वालों ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने तुरंत राहत नहीं दी तो विरोध प्रदर्शन और तेज़ किया जाएगा। हालांकि, इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक ज़िला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। इस विरोध प्रदर्शन ने एक बार फिर नयागढ़ ज़िले के ग्रामीण इलाकों में बढ़ते पीने के पानी के संकट को उजागर किया है, जिससे दूरदराज के गांवों में बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

पेयजल आपूर्ति योजना का काम पूरा

राउरकेला २७/०१ (संवाददाता): टिंबर कालोनी में 90 करोड़ की लागत पर वृहत जलापूर्ति परियोजना का काम वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। इसका काम पूरा हो गया है। इससे पेयजल आपूर्ति शुरू होने से वार्ड नंबर 13 के अमरनाथ बस्तीए पहाड़ी बस्तीए आनंद धाम बस्ती, चेनेया बस्ती, लोहरापाड़ा, तेलीपाड़ा, बंगाली पाड़ा, कुली खटाल, इंडियन आयल डिपो बस्ती, पटना खटाल, वैष्णो देवी रोड, नेपालीपाड़ा, जगन्नाथ कालोनी, टिंबर कालोनीए टीना कालोनी इलाके के दस हजार से अधिक लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा।

टिंबर माफिया ने वन विभाग से जब्त गाड़ी छीन ली

बालासोर २७/०१ (संवाददाता): ओडिशा के बालासोर जिले में शनिवार रात को कथित तौर पर लकड़ी माफिया ने वन विभाग के कर्मचारियों से जब्त लकड़ी से भरा एक वाहन छीन लिया और एक सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाया, जिससे संगठित लकड़ी तस्करी और फ्रंटलाइन वन कर्मचारियों पर हमलों को लेकर बढ़ती चिंताएं सामने आई

हैं। यह घटना पीठाहाटा पंचायत के सिमिलिगुडा इलाके में हुई, जहां नीलगिरी वन प्रभाग ने लकड़ी से लदे एक वाहन को जब्त करने के लिए कार्रवाई की थी। वन अधिकारियों के अनुसार, रिपोर्टिंग के समय बेरहामपुर पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराने की तैयारी थी। वाहन जब्ती अभियान बालासोर के वन रेंजर मनुवर खान ने बताया कि वन विभाग ने लकड़ी से लदे एक वाहन के बारे में मिली खास जानकारी पर कार्रवाई की। खान ने कहा, हमें सूचना मिली थी कि लकड़ी से लदा एक वाहन पलट गया है, जिसके बाद मैंने अपने कर्मचारियों को मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया और उन्हें बताया कि मैं जल्द ही बालासोर से पहुंचूंगा। उन्होंने आगे कहा, हालांकि, मौके पर पहुंचने पर हमारे कर्मचारियों ने पाया कि वाहन पलटा नहीं था और लकड़ी से लदा खड़ा था। वाहन से जुड़े लोग वन कर्मचारियों को देखकर भाग गए।

राउरकेला इस्पात संयंत्र ने देशभक्ति के हर्षोल्लास के साथ मनाया भारत का 77वाँ गणतंत्र दिवस

राउरकेला २७/०१ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) ने देशभक्ति के उत्साहपूर्ण वातावरण में भारत का 77वाँ गणतंत्र दिवस मनाया। इस्पात स्टेडियम में आयोजित समारोह में आरएसपी के 2000 से अधिक छात्र एवं कर्मचारी शामिल हुए, जिसे हजारों राउरकेलावासियों ने देखा।

निदेशक प्रभारी, आरएसपी, श्री आलोक वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड का निरीक्षण किया तथा ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल बैंड की धुन पर 61 टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। शहर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की स्काउट्स, गाइड्स, कॉम्बैट एवं सिविलियन टुकड़ियों के साथ-साथ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, आरएसपी की अग्निशमन सेवाओं तथा सेल हॉकी अकादमी की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट को और भी आकर्षक बनाया। दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्रों की टीम ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। मंच पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के उप निरीक्षक, श्री रतन कुमार भी उपस्थित थे। अपने गणतंत्र दिवस संबोधन में निदेशक प्रभारी ने कहा कि इस अवसर पर पूरे इस्पात शहर में देशभक्ति की भावना गूँज उठी है ।उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाली प्रतिष्ठित रचना %वंदे मातरम% की 150वीं वर्षगाँठ का विशेष उल्लेख किया और 1817 के ऐतिहासिक पाइका विद्रोह सहित इस आंदोलन में ओडिशा की अग्रणी भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने वीर बाजी राउत जैसे शहीदों के साथ-साथ महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साय को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनके सम्मान में उनकी जयंती पर एक सार्वजनिक उद्यान समर्पित किया गया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा ।

ओडिशा की महान स्वतंत्रता सेनानी रमादेवी के प्रेरणादायक शब्दों का हवाला देते हुए कि, स्वतंत्रता तभी सार्थक है, जब महिलाएँ पुरुषों के बराबर खड़ी हों, निदेशक प्रभारी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राउरकेला हाफ मैराथन में महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी देखी गई, जो धावकों का लगभग 30त्न थीं। निदेशक प्रभारी ने आरएसपी के प्रत्येक कर्मचारी

और अन्य सभी हितधारकों को कैलेंडर वर्ष 2025 में हासिल की गई उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बधाई दी, जिसमें कई रिकॉर्ड बने, नए मानदंड स्थापित हुए और नए उत्पादों ने उत्पाद श्रृंखला को समृद्ध किया।
निदेशक प्रभारी ने आगे कहा विकसित भारत – 2047 सभी 140 करोड़ भारतीयों का साझा सपना और जिम्मेदारी है। राउरकेला की इस धरती से, जहाँ देश की रीढ़ को मजबूत करने के लिए इस्पात का निर्माण होता है, आइए हम अपनी ऊर्जा, नवाचार और ईमानदारी के माध्यम से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भरता के शिखर को छू सके ।इस अवसर पर निदेशक प्रभारी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मियों को अति उत्कृष्ट एवं उत्कृष्ट पुरस्कार, संयंत्र के कार्मिकों को जवाहर पुरस्कार, आरएसपी गौरव पुरस्कार तथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टुकड़ियों को सम्मानित किया।

इसी प्रकार का एक और समारोह सेक्टर-22 मिनी स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहाँ श्री वर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड का निरीक्षण किया तथा 36 टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ टुकड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। निदेशक प्रभारी ने सुंदर मार्च पास्ट के लिए कनिष्ठ बालक (सिविलियन) वर्ग में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, कैंठाबासा और बालिका वर्ग में बिरसा मुंडा आदर्श बालिका उच्च विद्यालय को 10,000/- रुपये का विशेष पुरस्कार प्रदान किये। एसएसआरवी, इस्पात इंग्लिश मध्यम स्कूल, सेक्टर-22 के बैंड प्लाटून को भी कार्यक्रम में उनकी मनमोहक प्रस्तुती एवं सुसंगत धुन के लिए पुरस्कृत किया गया।

दोनों अवसरों पर अध्यक्ष (दीपिका महिला संघति),, श्रीमती नम्रता वर्मा, कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन), श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निदेशक (खान विकास- सीएमएलओ), श्री बी के गिरी, कार्यपालक निदेशक (संकार्य), श्री बिस्वरंजन पलई, कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन), श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक (खान), श्री एम पी सिंह, कार्यपालक निदेशक (परियोजनाएँ), श्री सुदीप पाल चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), श्री राजेश दासगुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा), डॉ. जे के आचार्य, दीपिका महिला संघति की सभी उपाध्यक्षाएँ, डॉ. (श्रीमती) प्रतिज्ञा पलई, श्रीमती रीता रानी, श्रीमती नवनीता पाल चौधरी आरएसपी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे। इन कार्यक्रमों का आयोजन आरएसपी के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से किया गया। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दीपिका महिला संघति द्वारा दीपिका महिला जागृति संस्थान, सेक्टर-2 में भी एक समान समारोह आयोजित किया गया। श्रीमती नम्रता वर्मा ने श्रीमती नवनीता पाल चौधरी एवं संघति की सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।